

मुकदमों का विवरण

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम

मल्लीकारजुन और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2011 की 2844) सितंबर 1, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे.]
हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: चाहे वह बच्चा जिसे यू/एस द्वारा विधायी वैधता प्रदान की गई हो। 16(1) या 16 (2), एस के कारण है। 16(3), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 माता-पिता की पैतृक/सह-आंशिक संपत्ति का हकदार है या बच्चा केवल माता-पिता की स्व-अर्जित/अलग संपत्ति का हकदार है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 -धारा 16-अमान्य और अमान्य विवाह के बच्चे-वैधता का सम्मेलन-वैध बच्चों के उत्तराधिकार अधिकार:

आयोजित किया गया: एस के संदर्भ में वैधता प्रदान करते हुए। 16(1) एक शादी से पैदा हुए बच्चे पर जो यू/एस शून्य है। 11, और एस के अंतर्गत। 16(2) एक अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को, जिसे यू/एस की निरर्थकता की डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है। 12, यह एस में निर्धारित है। 16(3) कि ऐसे बच्चे को माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा न कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर। 11, 12. [पैरा 54 (iii)]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 -धारा 3 (1) (जे)-'वैध संबंध द्वारा संबंधित'-
धाराओं के प्रावधानों का निर्माण। 3(1)(जे) परंतुक सहित:

आयोजित किया गया: एस द्वारा प्रदत्त वैधता। 16 एच. एम. ए. 1955 की धारा के अनुसार, एक शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को एच. एस. ए. 1956 के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए-वह बच्चा जो धारा 1 या धारा 2 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वैध है। 16 एच. एम. ए. का, एस. के प्रयोजनों के लिए। 3(1)(जे), 'वैध संबंध द्वारा संबंधित' स्पष्टीकरण के दायरे में आता है और 321 नहीं हो सकता है।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधान के प्रयोजनों के लिए एक 'अवैध बच्चे' के रूप में माना जाता है -एस. 16.[पैरा 54 (iv)]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम **1956** -धारा **6**-सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण-धाराओं का प्रतिस्थापन। **6 2005** के अधिनियम **39** द्वारा-प्रभावी अधिनियम:

आयोजित किया गया:एस के प्रतिस्थापन द्वारा। 6, एस की उप-धारा (1) द्वारा दर्शाए गए तरीके से बेटों के समान अधिकार बेटियों को दिए गए हैं। 6 – एस की उप-धारा (3) के संदर्भ में। 6 जैसा कि संशोधित किया गया है, 2005 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद एक हिंदू की मृत्यु होने पर मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा विभाजित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा-हस्तांतरण के उक्त नियम को मानक बनाया गया है-स के प्रतिस्थापन से पहले। 6 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा, धारा 6 ने सह-सदस्य के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा एक पुरुष हिंदू की मिताक्षर सह-सदस्य संपत्ति में ब्याज के हस्तांतरण को निर्धारित किया-उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण का अपवाद वह था जहां मृतक ने अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट महिला रिश्तेदार या प्रथम वर्ग में एक पुरुष रिश्तेदार को एक महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करते हुए जीवित छोड़ दिया था, जिस स्थिति में मिताक्षर सह-सदस्य संपत्ति में मृतक का हित वसीयती या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा विभाजित होगा। [पैरा 54 (v), (vi)]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम **1956** -धारा **6**-सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण-काल्पनिक विभाजन के आधार पर हिस्सेदारी का प्रमाणीकरण:

आयोजित किया गया:मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में एक हिंदू के हित के हस्तांतरण का प्रावधान करते हुए, 2005 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा मृत्यु हो जाती है, धारा 6 (3) में एक विधि ी आदेश दिया गया है कि सह-पक्षीय संपत्ति को इस तरह विभाजित किया गया माना जाएगा जैसे कि कोई विभाजन हुआ हो-किसी मृत हिंदू मिताक्षर सह-पक्षकार के हित का पता लगाने के लिए, विधि सह-पक्षकार की मृत्यु से तुरंत पहले संबंध की स्थिति की धारणा को अनिवार्य करता है-एक बार जब संपत्ति में मृतक का हिस्सा जो उसे आवंटित किया जाता, अगर उसकी मृत्यु से तुरंत पहले विभाजन हुआ होता, तो उसके उत्तराधिकारियों को वैधता प्रदान की जाती है। 6 एच. एम. ए. का, उस संपत्ति में अपने हिस्से का हकदार होगा जो अनुमानित विभाजन पर मृतक को आवंटित किया गया होता, यदि यह हुआ होता। [पैरा 54 (viii), (ix)]

322 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम **1956** -धारा **6 (3)**-हिंदू विवाह अधिनियम, **1955** - एस. **16** -एच. एम. ए. **1955** की धारा **16 (3)** और अनु. **6(3)** एच. एस. ए. **1956**, यदि असंगत है:

आयोजित किया गया:एस के बीच कोई विसंगति नहीं है। 6(3) एच. एम. ए. 1955 और एस. 6(3) एच. एस. ए. 1956-एच. एस. ए. 1956 के प्रावधानों को एस. में जनादेश के साथ

सुसंगत बनाया जाना चाहिए। 16(3) एच. एम. ए. 1955 जो इंगित करता है कि एक बच्चा जिसे धाराओं की उप-धाराओं (1) और (2) के अंतर्गत वैधता प्रदान की गई है। 16, माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके अधिकारों का हकदार नहीं होगा-माता-पिता की संपत्ति, जहां माता-पिता का मिताक्षर विधि के अंतर्गत शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में हित था, का पता उप-धारा (3) [पैरा 54 (x)] के स्पष्टीकरण के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए।

निर्णय /आदेश-इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संदर्भित निर्णय में रेवनसिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन ने कहा कि अवैध बच्चों को अपने माता-पिता की सह-आंशिक संपत्ति में अधिकार होगा, जो स्वयं अर्जित या पैतृक होगी-पुनर्विचार:

आयोजित किया गया:संदर्भित निर्णय में कुछ हद तक विरोधाभास है जिसे स्पष्ट करने और शांत करने की आवश्यकता है-इस प्रकार, संदर्भ ने यह मानते हुए उत्तर दिया कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने मृत माता-पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं, न कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में। [पैरा 53]

मिताक्षर विधि -संयुक्त हिंदू परिवार-का विवरण:

आयोजित किया गया:इसमें ऐसे पुरुष सदस्य शामिल होते हैं जो एक सामान्य पुरुष पूर्वज के वंशज होते हैं, अपनी माताओं, पत्नियों या विधवाओं और अविवाहित बेटियों के साथ-साथ संयुक्त हिंदू परिवार को 'एक बड़ा निकाय' के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें सपींदाशिप या पारिवारिक संबंधों द्वारा एकजुट व्यक्तियों का एक समूह होता है। [पैरा 21]

मिताक्षर विधि -हिंदू सह-पक्षीय-की संरचना:

आयोजित किया गया:इसमें एक प्रतिनिधि और तीन वंश शामिल हैं-हिंदू सह-सदस्य एक ऐसा निकाय है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार की तुलना में संकीर्ण है-2005 से पहले, इसमें केवल बेटे, पोते और परपोते शामिल थे जो संयुक्त संपत्ति के धारक थे-सह-सदस्य की पहचान यह है कि तीसरी पीढ़ी तक एक वंशानुगत पुरुष वंशज एक स्वतंत्र 323 प्राप्त करेगा।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस।

जन्म से स्वामित्व का अधिकार और मृतक सदस्य का हित उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा और सह-आंशिक संपत्ति में विलय हो जाएगा। [पारस 22-25]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, **1956** -धारा **6**-मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण-**2005** के अधिनियम **39** द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले और धारा **6** के प्रतिस्थापन के बाद की स्थिति। **6 2005** के

अधिनियम **39** द्वारा-मिताक्षर विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवारों में बेटियों पर सह-सदस्य अधिकार-समझाया गया।[पारस

26-41]

मिताक्षर विधि -उसके तहत शासित संयुक्त हिंदू परिवार-उस वर्ग के संयुक्त हिंदू परिवारों के संबंध में एच. एस. ए. **1956** के प्रावधान-हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, **1956** की व्याख्या।[पैरा **55**] शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

जिनिया केओटिन बनाम कुमार सीताराम मांझी (2003) 1 एस. सी. सी. 730:[2002] 5 पूरक।एससीआर 689; नीलम्मा बनाम सरोजम्मा (2006) 9 एससीसी 612; भरत माथा बनाम आर विजय रंगनाथन (2010) 11 एस. सी. सी. 483:[2010] 7 एस. सी. आर. 154; रेवनसिदप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) 11 एस. सी. सी. 1:[2011] 4 एससीआर 675; परायणकंडियाल एरावथ कनप्रवन कल्लियानी अम्मा (श्रीमती) बनाम के देवी

(1996) 4 एससीसी 76:[1996] 2 पूरक।एस. सी. आर. 1; अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ (2020) 13 एस. सी. सी. 585:[2019] 12 एससीआर 30; सुशील कुमार बनाम राम प्रकाश (1988) 2 एससीसी 77:[1988] 2 एस. सी. आर. 623; श्रीमती सीताबाई बनाम रामचंद्र (1969)

2 एससीसी 544:[1970] 2 एस. सी. आर. 1; गौली बुद्धन्ना बनाम सी. आई. टी., मैसूर, बेंगलोर

एआईआर 1966 एससी 1523:[1966] एस. सी. आर. 224; सुरजित लाल छाबड़ा बनाम आयकर आयुक्त बॉम्बे (1976) 3 एस. सी. सी.[1976] 2 एससीआर 164; विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) 9 एससीसी 1:[2020] 10 एस. सी. आर. 135; भारतीय स्टेट बैंक बनाम घमंडीराम (1969) 2 एस. सी. सी. 33:[1969] 3 एससीआर 681; नियंत्रक

एस्टेट ड्यूटी, मद्रास बनाम अल्लादी कुप्पुस्वामी (1977) 3 एस. सी. सी. 385:[1977] 3 एस. सी. आर. 721; महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम राव देशमुख

(1985) 2 एससीसी 321:[1985] 3 एससीआर 358; वेल्लिकन्नू बनाम आर. सिंगापेरुमल (2005) 6 एससीसी 622:[2005] 1 पूरक।एससीआर 160; रोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह (2013) 9 एससीसी 419:[2013] 7 एस. सी. आर. 897; कटामा नचियर बनाम राजा

शिवगंगा का 1863 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 11; गुरुपद खंडप्पा बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदुम (1978) 3 एस. सी. सी. 383:[1978] 3 एस. सी. आर. 761; शांताराम

तुकाराम पाटिल बनाम दग्गुबाई तुकाराम पाटिल 1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 9:1987 माह एलजे179; भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965)

2 एस. सी. आर. 837-संदर्भित।

324 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील अपीलीय अधिकारिता 2011 की सिविल अपील सं. 2844।कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 07.11.2008 के निर्णय और आदेश से, 2006 के आर. एस. ए. No.550 में गुलबर्गा में सर्किट बेंच।

सह

सिविल अपील सं. 2021 का 2312, 2018 का एसएलपी (सी) सं. 23397-98, सिविल अपील 2014 का No.7318, एसएलपी (सी) 2016 का No.81, सिविल अपील 2019 का No.4398, एसएलपी (सी) 2016 का Nos.14176-77, 2017 का 27834 और 2021 का 1573-74

रूप:

सुश्री किरण सूरी, टी. एस. आर. वेंकटरमण सीनियर एड., सुश्री मंजू जेटली, विवेक सोलशे, अमोल बी. करंडे, राज साहेब पाटिल, नरेंद्र राव ठाणेयर, वरुण सोलशे, शिवांगी सिंह, आदित्य यादव, सुश्री पलक माथुर, सत्यजीत ए. देसाई, सिद्धार्थ गौतम, अभिनव के. मुत्यालवार, गजानन एन. तीर्थकर, विजय राज सिंह चौहान, सुश्री अनघा एस. देसाई, सुधांशु एस. चौधरी, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, अमान श्रेयस, महेश पी. शिंदे, सुश्री रुचा ए. पांडे, एम. वीरारागवन, यशस्विनी चौहान, एस. जे. अमित, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, सुश्री विदुषी गर्ग, पूर्वेश बटान, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, रणबीर सिंह यादव, प्रतीक यादव, पूरन मल सैनी, सुश्री अंजू के वर्की, रितेश पाटिल, योगेश यादव, पति राज यादव, मोहम्मद शाहरुख, आर सतीश, जीएसवाई, सुश्री जानकी देवी, अभय सिंह यादव, निखिल मजीठिया, नीलेश्वर पवनी, हर्षित अग्रवाल, आशीष गुप्ता, कमल कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।के. राधाकृष्ण, सुश्री वी. मोहना, विवेक चिब, ए. आई. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, श्रीमती रजनी।के. प्रसाद, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री आभा आर. शर्मा, अपूर्व कुरुप, रोहित अनिल राठी, विजय कुमार पानपालिया, चंद्र प्रकाश, पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, अरिंदम घोष, कार्तिक जयशंकर, अंशुमान बहादुर, पी. बी. शशांक, आबिद अली बीरन पी., सुश्री भव्य पांडे, सुश्री स्नेहा बोटवे, सुश्री याशिका शर्मा, बी रघुनाथ, सुश्री विष्णुशंकर, श्रीमती एन. सी. कविता, सुश्री उन्नति झुझुनवाला, सुश्री मानसी गुप्ता, विजय कुमार, एस. राजप्पा, वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पाराशर, एन. जे.

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस।

सुश्री रुचा प्रवीण मंडलिक, सुश्री हरसिम्रान कौर राय, मोहित गौतम, अपूर्व शर्मा, शांतकुमार वी महाले, राजेश महाले, श्रीराम पी., सुश्री ज्योतिका कालरा, जॉयदीप मुखर्जी, सुश्री अन्वेशा देब, लक्ष्मी रमन सिंह, एच. चंद्र शेखर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई टेबल ऑफ कंटेंट

ए. तीन न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ. 3 बी. वैधानिक वैधता प्रदान करना. 6 सी. माता-पिता की संपत्ति में या उसके अधिकार. 14 डी. संदर्भ में मुद्दे. 16 ई. प्रस्तुतियाँ:.....17 एफ. मिताक्षर के अंतर्गत संयुक्त हिंदू परिवार और सह-सदस्य. 23 जी. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956.27 एच. माता-पिता की संपत्ति. 39 आई. वैधता और सह-सदस्य. 46 जे. संदर्भित निर्णय पर पुनर्विचार किया गया:.....51 के. निष्कर्ष. 55

ए. तीन न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ

1. माता-पिता से पैदा हुआ बच्चा, जिसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत अमान्य है, धारा 16 (1) द्वारा "वैध" घोषित किया जाता है, यदि इस तरह के विवाह का कोई बच्चा वैध होता, यदि विवाह वैध होता।" इसी तरह, जहां शून्यता की एक डिक्री है

1 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (एच. एम. ए.)

326

/

[2023] 14 एस सी आर।

धारा 12 के अंतर्गत एक अमान्य विवाह के संबंध में दिया गया है, एक बच्चा "डिक्री बनाए जाने से पहले पैदा हुआ या गर्भ धारण किया गया" "उनका वैध बच्चा माना जाता है" यदि ऐसा बच्चा विवाह के पक्षों का वैध बच्चा होता यदि विवाह को रद्द करने के बजाय भंग कर दिया गया होता। धारा 16 (3) में कहा गया है कि किसी ऐसे विवाह के बच्चे को, जो अमान्य या अमान्य है या जिसे रद्द करने की डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है, माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन कानून के अधिनियमन के लिए ऐसा बच्चा अपने माता-पिता की वैध संतान नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होगा।

2. इस न्यायालय के कई निर्णयों ने माता-पिता के बच्चों को प्रदत्त संपत्ति अधिकारों की प्रकृति पर विचार किया है, जिनकी शादी या तो अमान्य है या जिनके संबंध में धारा 12 के अंतर्गत निरर्थकता की डिक्री पारित की गई है।

जिनिया केओटिन बनाम कुमार सीताराम मांझी **3** मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि

केवल इसलिए कि एक शून्य और अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को धारा 16 के अंतर्गत विशिष्ट रूप से संरक्षित किया गया है, उन्हें माता-पिता की पैतृक संपत्ति की विरासत के उद्देश्य से वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि धारा 16 (3) में विधायिका के स्पष्ट अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, एक अमान्य विवाह या एक अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को, जिसके संबंध में शून्यता की डिक्री पारित की गई है, पैतृक या सह-आंशिक संपत्ति के संबंध में विरासत का कोई अधिकार नहीं होगा। जिनिया के ओटिन में निर्णय के बाद दो निर्णय लिए गए

नीलम्मा बनाम सरोजम्मा **5** और बाद में भारत मठ में न्यायाधीशों की पीठ

वी आर विजया रंगनाथन 6. पहले के दो फैसलों को स्वीकार करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि "अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा पैतृक सह-आंशिक संपत्ति में विरासत का दावा करने का हकदार नहीं है, बल्कि केवल स्व-अर्जित संपत्तियों में हिस्से का दावा करने का हकदार है।" 7

3. जिनिया के ओटिन, नीलम्मा में निर्णयों की शुद्धता,

2 एच. एम. ए. 3 (2003) 1 एस. सी. सी. 730 की धारा 16 (2)

4 पृष्ठ 732 पर, पैरा 2

5 (2006) 9 एस. सी. सी. 612 6 (2010) 11 एस. सी. सी. 483 7 पृष्ठ 513 पर, पैरा 29, 327

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लिकार्जुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 328

और भारत मठ को रेवनासिदप्पा बनाम मल्लिकार्जुन 8 में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदेह किया गया है। पहले के फैसलों की शुद्धता को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए अपने आदेश में, न्यायालय ने निम्नलिखित आधार पर अपने संदेह को प्रस्तुत किया है:

(i) धारा 16 (3) 'पैतृक या स्व-अर्जित' संपत्ति के साथ 'संपत्ति' अभिव्यक्ति को योग्य नहीं बनाती है। यह एक स्पष्ट आदेश निर्धारित करता है कि ऐसे बच्चे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति के हकदार हैं, न कि किसी अन्य संबंध की।

(ii) एक बार जब एक अमान्य विवाह (या एक अमान्य विवाह जिसे अमान्य घोषित किया गया है) से पैदा हुए बच्चों को धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा वैध घोषित किया जाता है, तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और उनके माता-पिता की संपत्ति में सभी अधिकारों के उद्देश्य से अन्य वैध बच्चों के साथ समान होगा, दोनों स्व-अर्जित और पैतृक 9; (iii) धारा 16 को 1976 के अधिनियम 68 द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन के परिणामस्वरूप, सामान्य विधि का विचार है कि एक के बच्चे

विवाह जो अमान्य या अमान्य है 'अवैध' है 'इप्सो जूर'

10 को पूरी तरह से बदलना होगा। विधि का सामाजिक रूप से लाभकारी उद्देश्य इस तरह के विवाहों के बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली अवैधता के कलंक को दूर करना है, क्योंकि बच्चे स्वयं निर्दोष हैं।

((iv) धारा 16 (3) का लाभ केवल तभी मिलता है जब विवाह होता है, लेकिन विवाह या तो अमान्य है या कानून के प्रावधानों को देखते हुए अमान्य है।

((v) संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के मामले में, एक अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्से के हकदार होंगे, लेकिन अपने अधिकार में नहीं।

“38...तार्किक रूप से, पैतृक संपत्ति के विभाजन पर, ऐसे बच्चों के माता-पिता के हिस्से में आने वाली संपत्ति को उनकी स्व-अर्जित और पूर्ण संपत्ति माना जाता है।

8 (2011) 11 एस. सी. सी. 1 9 पैरा 29 पेज 9 10 पैरा 36 पेज 10 पर

/

[2023] 14 एस सी आर।

संशोधन को ध्यान में रखते हुए, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि ऐसे बच्चों का ऐसी संपत्ति में कोई हिस्सा क्यों नहीं होगा क्योंकि ऐसे बच्चों को संशोधित विधि के अंतर्गत वैध विवाह के वैध वसंत के बराबर माना जाता है। संशोधन के बाद भी एकमात्र सीमा यह प्रतीत होती है कि अपने माता-पिता के जीवनकाल के दौरान ऐसे बच्चे विभाजन की मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।”

((vi) यद्यपि माता-पिता के बीच संबंध को विधि द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, ऐसे संबंध में बच्चे के जन्म को ऐसे संबंध से स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। धारा 16 (3) की व्याख्या स्थिति और अवसर की समानता के साथ-साथ व्यक्तिगत गरिमा के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।

((vii) ऐसे संबंध में पैदा हुआ बच्चा निर्दोष है और वह उन सभी अधिकारों का हकदार है जो वैध विवाह में पैदा हुए अन्य बच्चों को इस सीमा के अधीन रहते हुए दिए जाते हैं कि अधिकार माता-पिता की संपत्ति में निहित है; और

((viii) धारा 16 (3), जैसा कि संशोधित किया गया है, अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के संपत्ति अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, सिवाय इसके कि यह उनके माता-पिता की संपत्ति तक सीमित हो। इसलिए, ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा, चाहे वह स्व-अर्जित हो या पैतृक। इस प्रकार, वर्तमान संदर्भ इस तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उत्पन्न होता है।

B. वैधानिक वैधता प्रदान करना

4. एच. एम. ए. 1955 की धारा 5 विनिर्दिष्ट है, जैसा कि सीमांत नोट इंगित करते हैं,

‘हिंदू विवाह’ 11 के लिए शर्तें।

11 5. हिंदू विवाह के लिए शर्तें।- यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है तो किसी भी दो हिंदुओं के बीच विवाह किया जा सकता है, अर्थात्:-

(i) विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित नहीं है; (ii) विवाह के समय, न तो पक्ष -

(ए) मानसिक अस्वस्थता के परिणामस्वरूप इसे वैध सहमति देने में असमर्थ है; या (बी) हालांकि एक वैध सहमति देने में सक्षम है, इस तरह के मानसिक विकार से या इस हद तक कि विवाह और 329 के प्रजनन के लिए अयोग्य है।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 330

5. धारा 11 में कहा गया है कि अधिनियम के प्रारंभ के बाद संपन्न विवाह अमान्य और अमान्य होगा और इस तरह इसे अमान्य की डिक्री द्वारा घोषित किया जाएगा यदि (i) विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी रहता है; (ii) पक्ष निषिद्ध संबंध की डिग्री के भीतर हैं, सिवाय इसके कि उन्हें नियंत्रित करने वाली प्रथा या उपयोग विवाह की अनुमति देता है; और (iii) पक्ष एक-दूसरे के आश्रित हैं, जब तक कि उन्हें नियंत्रित करने वाली प्रथा या उपयोग विवाह की अनुमति नहीं देता है।

6. धारा 12 उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करती है जिनमें विवाह अमान्य होगा और रद्द करने की डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकता है।

बच्चे; या

(ग) पागलपन के बार-बार हमलों के अधीन रहा है;

((ग) विवाह के समय दूल्हे की आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होगी।

((iv) पक्षकार तब तक निषिद्ध संबंध के स्तर के भीतर नहीं हैं जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाली प्रथा या उपयोग दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता है।

(v) पक्ष एक-दूसरे के सपिंडा नहीं हैं, जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाली प्रथा या उपयोग दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता है।

12 11. शादियों से दूर रहें।- इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद संपन्न कोई भी विवाह अमान्य होगा और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ प्रस्तुत याचिका पर, यदि यह धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है, तो इसे शून्य की डिक्री द्वारा घोषित किया जा सकता है।

13 12. रद्द किए जाने वाले विवाह।— (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न किया गया कोई भी विवाह अमान्य होगा और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर रद्द करने की डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकता है, अर्थात् -

(क) कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाह पूरा नहीं हुआ है; या

(ख) कि विवाह धारा 5 के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन है; या

(ग) जहाँ याचिकाकर्ता की सहमति, या जहाँ धारा 5 के अंतर्गत याचिकाकर्ता की शादी में अभिभावक की सहमति की आवश्यकता थी क्योंकि यह बाल विवाह प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 2) के प्रारंभ

से तुरंत पहले थी, ऐसे अभिभावक की सहमति समारोह की प्रकृति या प्रतिवादी से संबंधित किसी भी भौतिक तथ्य या परिस्थिति के रूप में बलपूर्वक या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी; या (घ) कि प्रतिवादी विवाह के समय याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, विवाह को रद्द करने के लिए कोई याचिका नहीं -

(क) उप-धारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर, विचार किया जाएगा यदि-(i) बल के कार्य करना बंद करने के एक वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई याचिका या, जैसा भी मामला हो, धोखाधड़ी का पता चला था; या

(ii) याचिकाकर्ता, अपनी पूरी सहमति से, बल के काम करना बंद करने के बाद या, जैसा भी मामला हो, पति या पत्नी के रूप में विवाह के दूसरे पक्ष के साथ रहा है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

7. धारा 16 जैसा कि इसे मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, निम्नानुसार प्रदान की गई है:

“16. अमान्य और अमान्य विवाहों के बच्चों की वैधता।—जहां धारा 11 या धारा 12 के अंतर्गत किसी भी विवाह के संबंध में निरर्थकता की डिक्री दी जाती है, जो डिक्री बनाए जाने से पहले पैदा हुआ या गर्भ धारण किया गया कोई भी बच्चा होता, जो विवाह के पक्षकारों का वैध बच्चा होता, अगर इसे अमान्य घोषित किए जाने या निरर्थकता की डिक्री द्वारा रद्द किए जाने के बजाय भंग कर दिया गया होता, तो निरर्थकता की डिक्री के बावजूद उनका वैध बच्चा माना जाएगा:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी विवाह के किसी ऐसे बच्चे को प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा जिसे किसी भी मामले में माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके लिए कोई अधिकार अमान्य या रद्द घोषित किया जाता है, लेकिन इस अधिनियम के पारित होने के लिए, ऐसा बच्चा अपने माता-पिता की वैध संतान नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता। ”

8. जबकि धारा 16, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, अमान्य और अमान्य विवाह के बच्चों की वैधता की रक्षा करता था, इसकी प्रयोज्यता चार आवश्यकताओं द्वारा सशर्त थी अर्थात्:

((i) विवाह का अस्तित्व;

((ii) विवाह धारा 11 के अंतर्गत अमान्य होना चाहिए या धारा 12 के अंतर्गत अमान्य होना चाहिए।

((iii) धारा 11 या धारा 12 के अंतर्गत विवाह को रद्द करने के लिए एक डिक्री होनी चाहिए; और

((iv) बच्चे को जन्म देने या गर्भ धारण करने से पहले होना चाहिए था।

हो सकता है, धोखाधड़ी का पता चला हो;

(ख) उप-धारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि न्यायालय -

(i) कि विवाह के समय याचिकाकर्ता कथित तथ्यों से अनजान था; (ii) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले संपन्न विवाह के मामले में ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर और विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे प्रारंभ के बाद संपन्न विवाह के मामले में कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आधार के अस्तित्व का पता चलने के बाद से याचिकाकर्ता की सहमति से वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। "

331

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 332

फरमान जारी किया गया।

9. जिस तरह से धारा 16 का मसौदा तैयार किया गया था, उसके दो परिणाम हुए:सबसे पहले, एक अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को दी गई वैधता की स्थिति विवाह को रद्द करने की डिक्री द्वारा रद्द किए जाने पर सशर्त थी।रद्द करने के आदेश के बिना, बच्चा 'अवैध' बना रहेगा।यदि पक्षों ने न्यायालय का रुख नहीं किया था और डिक्री प्राप्त नहीं की थी, तो धारा 16 के अंतर्गत संरक्षण उपलब्ध नहीं था।दूसरा, अमान्य या अमान्य विवाहों से पैदा हुए बच्चों को कृत्रिम रूप से दो समूहों में विभाजित किया गया था, वे जो कानून के अधिनियमन से पहले किए गए विवाह से पैदा हुए थे और जो इसके अधिनियमन के बाद पैदा हुए थे।

10. धारा 16 के पूर्ववर्ती प्रावधानों में विसंगतियों को परायणकंडियाल में इस न्यायालय के निर्णय में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था।

एरावथ कनप्रवन कल्लियानी अम्मा (श्रीमती) बनाम के देवी **14.न्यायालय** ने कहा:

“58. विधायकों की दूरदर्शिता के बावजूद, संसद की मंशा को अधिनियम में पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं किया जा सका, जो दुर्भाग्य से विधेयक का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्तियों और उसमें निहित विभिन्न प्रावधानों के लिए पर्याप्त था।परिणाम चौंकाने वाले थे। चूंकि वैधता का नियम विवाह (शून्य या अमान्य) को रद्द करने की डिक्री द्वारा रद्द किए जाने पर निर्भर था, इसलिए इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे अवैध बने रहेंगे यदि रद्द करने की डिक्री पारित नहीं की गई थी, जो संयोग से, हमेशा मामला होगा, यदि पक्ष न्यायालय का दरवाजा नहीं उठाते हैं।दूसरा परिणाम यह हुआ कि अवैध बच्चे दो समूहों में विभाजित हो गए-वे जो अधिनियम से पहले हुए विवाह से पैदा हुए थे और वे जो अधिनियम के बाद हुए विवाह से पैदा हुए थे। नाजायज बच्चों के इन दो समूहों के बीच कोई भेद नहीं था, लेकिन वे

उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा के कारण शत्रुतापूर्ण विधायी भेदभाव को स्वीकार करने लगे। वास्तव में, भाषा मानव विचार की अभिव्यक्ति के लिए एक अपूर्ण साधन है। "

11. भारत के विधि आयोग की 59 वीं रिपोर्ट (मार्च 1974) में अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.36 में विस्तार से बताया गया है कि चार संभावित थे

14 (1996) 4 एससीसी 76

/

[2023] 14 एस सी आर।

गोद लेने के लिए परिसर, जो इस प्रकार थे: " 2.36.... एक अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों की स्थिति के संदर्भ में, सैद्धांतिक रूप से, चार प्रमुख विचार संभव हैं:-

(i) एक दृष्टिकोण यह है कि ऐसे बच्चों को अवैध माना जाना चाहिए, क्योंकि एक अमान्य विवाह का, विधि ी रूप से, कोई अस्तित्व नहीं है, और इस तरह के विवाह के बच्चों को केवल फी लियस नुलियस माना जा सकता है;

((ख) दूसरा विचार यह है कि उन्हें अपने माता-पिता का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार होना चाहिए, जैसे कि वे वैध हों, बशर्ते कि माता-पिता ने किसी भी बाधा की जानकारी के बिना विवाह किया हो।

(iii) तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार, उन्हें, सभी मामलों में, अपने माता-पिता के उत्तराधिकारी होने का हकदार होना चाहिए जैसे कि वे वैध थे;

((iv) एक चौथा दृष्टिकोण हो सकता है, अर्थात्, उन्हें सभी मामलों में अन्य संबंधों में सफल होने का अधिकार होना चाहिए। "

विधि आयोग ने नोट किया कि विधायिका ने तीसरा दृष्टिकोण अपनाया था। रिपोर्ट में कहा गया है:

"हालाँकि, हिंदू विवाह अधिनियम ने पहले ही तीसरे दृष्टिकोण को अपना लिया है, अगर यह अब दूसरे दृष्टिकोण पर लौटता है तो यह एक प्रतिगामी कदम होगा। इसके अलावा, तीसरा दृष्टिकोण विवाह के निर्दोष जन्म के लिए बिल्कुल अधिक उचित है, और आधुनिक सामाजिक धारणाओं के अनुरूप है। इसलिए, हमारी राय है कि दूसरे दृष्टिकोण पर लौटने का कोई औचित्य नहीं है। "

धारा 16 को 1976 के अधिनियम 68 द्वारा संशोधित किया गया था। जैसा कि संशोधित किया गया है, धारा 16 निम्नलिखित प्रावधान करती है:

"16. अमान्य और अमान्य विवाहों के बच्चों की वैधता।—(1)

इसके बावजूद कि धारा 11 के अंतर्गत विवाह अमान्य है, ऐसे विवाह का कोई भी बच्चा जो वैध होता यदि विवाह वैध होता, वैध होगा, चाहे वह बच्चा विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 68) के प्रारंभ से पहले या बाद में पैदा हुआ हो, और क्या इस अधिनियम के अंतर्गत उस विवाह के संबंध में निरर्थकता की डिक्री दी गई है या नहीं और क्या इस अधिनियम के अंतर्गत याचिका के अलावा विवाह को अमान्य माना जाता है या नहीं।

333

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 334

(2) जहां धारा 12 के अंतर्गत अमान्य विवाह के संबंध में निरर्थकता की डिक्री दी जाती है, वहां डिक्री बनाए जाने से पहले पैदा हुआ या गर्भ धारण किया हुआ कोई भी बच्चा, जो विवाह के पक्षकारों का वैध बच्चा होता यदि डिक्री की तारीख को इसे रद्द करने के बजाय भंग कर दिया गया होता, तो निरर्थकता की डिक्री के बावजूद उनकी वैध संतान मानी जाएगी।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विवाह के किसी ऐसे बच्चे को, जो अमान्य है या जो धारा 12 के अंतर्गत निरर्थकता की डिक्री द्वारा निरस्त कर दिया गया है, माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके लिए कोई अधिकार प्रदान करता है, किसी भी मामले में जहां, इस अधिनियम के पारित होने के अलावा, ऐसा बच्चा अपने माता-पिता की वैध संतान नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता। "

12. कल्लियानी अम्मा (उपरोक्त) मामले में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा 16 को मूल रूप से 'वैधता का दर्जा प्रदान करने के मामले में अवैध बच्चों के दो समूहों के बीच भेदभाव' के रूप में अधिनियमित किया गया था और इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। न्यायालय ने कहा कि अपने पहले के रूप में, धारा 16 को धारा 11 और 12 से जोड़ा गया था। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रतिस्थापित धारा 16 संवैधानिक है, न्यायालय ने उप-धारा 1 में अबाधित प्रावधान के प्रभाव का विश्लेषण किया। न्यायालय ने कहा:

“78. धारा 16 (1) में प्रयुक्त शब्द "इसके बावजूद कि धारा 11 के अंतर्गत विवाह अमान्य है" निस्संदेह निम्नलिखित को इंगित करते हैं:

(क) धारा 16 (1) को धारा 11 से अलग किया गया है।

(ख) धारा 16 (1) के प्रावधान, जो अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करने का इरादा रखते हैं, धारा 11 के बावजूद पूरे जोश के साथ काम करेंगे, जो केवल उन विवाहों को रद्द करता है जो अधिनियम के प्रवर्तन के बाद किए जाते हैं और जिनके प्रदर्शन में धारा 5 का उल्लंघन किया जाता है।

(ग) धारा 16 (1) में संशोधन की तारीख से पहले या बाद में पैदा हुए बच्चों को वैधता का लाभ प्रदान किया गया है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

(घ) गड़बड़ी या बुराई जो असंशोधित धारा 16 की असंवैधानिकता का आधार थी, उसे संशोधन द्वारा प्रभावी रूप से हटा दिया गया है। (ई) धारा 16 (1) अब अपने बल पर खड़ी है और अन्य धाराओं से स्वतंत्र रूप से काम करती है जिसके परिणामस्वरूप यह संवैधानिक रूप से मान्य है क्योंकि यह अवैध बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करती है और उन्हें वैधता प्रदान करने के लिए एक समूह के रूप में वर्गीकृत करती है।

इसलिए, धारा 16, अपने वर्तमान रूप में, संविधान के अधिकार के बाहर नहीं है। "

धारा 16 को अंतर-अधिकार माना गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 16 एक कानूनी अधिनियम लागू करती है: 'न्यायिक न्याय' के एक नियम द्वारा विधायिका ने प्रावधान किया है कि बच्चे, हालांकि "अवैध" हैं, फिर भी, विवाह के अमान्य या अमान्य होने के बावजूद, उन्हें वैध माना जाएगा। धारा 16 में कानूनी निर्णय की व्याख्या करते हुए, कल्लियानी अम्मा में न्यायालय ने कहा कि "अवैध बच्चों को, उनके माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार सहित सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, वैध माना जाना चाहिए"। तथापि, "वे इस नियम के आधार पर किसी अन्य संबंध के गुणों में सफल नहीं हो सकते हैं, जो अपने संचालन में, माता-पिता के गुणों तक सीमित है":

"82. धारा 16 में निहित कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, अवैध बच्चों को, अपने माता-पिता की संपत्तियों के उत्तराधिकार सहित सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, वैध माना जाना चाहिए। हालांकि, वे इस नियम के आधार पर किसी अन्य संबंध की संपत्तियों में सफल नहीं हो सकते हैं, जो अपने संचालन में माता-पिता की संपत्तियों तक सीमित है। "

13. एच. एम. ए. 1955 की धारा 2 में अधिनियम 15 को लागू करने के प्रावधान हैं। स्पष्टीकरण के खंड (ए) अंतर्गत जहां एक के माता-पिता दोनों

15 2. अधिनियम का अनुप्रयोग-(1) यह अधिनियम लागू होता है।

(क) वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए जो धर्म के किसी भी रूप या विकास में हिंदू है,

(ख) किसी भी व्यक्ति को जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, और

(ग) उन क्षेत्रों में अधिवासित किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके लिए यह अधिनियम विस्तारित है, जो धर्म द्वारा मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि ऐसा कोई 335

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 336

बच्चे हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख 'धर्म से' हैं, बच्चा, चाहे वैध हो या अवैध, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख भी होगा, जैसा भी मामला हो। खंड (बी) के तहत जहां माता-पिता अंतर्गत से कोई एक चार धर्मों अंतर्गत से किसी एक को मानता है, बच्चे को हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख माना जाएगा, चाहे वह बच्चा वैध हो या अवैध। स्पष्टीकरण के खंड (ए) और (बी) से संकेत मिलता है कि एक बच्चे की वैधता, जिसके माता-पिता में से एक या दोनों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म का पालन करते हैं, बच्चे पर अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक नहीं है।

14. धारा 16 की उप-धारा (1) एक अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैधता की घोषणा ("वैध होगी") प्रदान करती है, जबकि उप-धारा (2) में संबंधित प्रावधानों में परिकल्पित स्थितियों में एक अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे ("उनकी वैध संतान मानी जाएगी") की वैधता का एक महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है। उप-धारा (1) ऐसी स्थिति को नियंत्रित करती है जहां धारा 11 के अंतर्गत विवाह अमान्य है। उप-धारा (2) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां धारा 12 के अंतर्गत अमान्य विवाह के संबंध में निरर्थकता की डिक्री दी जाती है। उप-धारा (1) घोषणा करती है कि धारा 11 के अंतर्गत अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा "वैध होगा" यदि ऐसा बच्चा वैध होता यदि विवाह वैध होता। उप-धारा (1) के अंतर्गत वैधता की घोषणा संचालित करती है कि क्या

यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता तो व्यक्ति हिंदू विधि या उस विधि के हिस्से के रूप में किसी भी प्रथा या उपयोग द्वारा शासित नहीं होता।

स्पष्टीकरण .- धर्म के आधार पर निम्नलिखित व्यक्ति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं, जैसा भी मामला हो सकता है:

- (क) कोई भी बच्चा, वैध या अवैध, जिसके माता-पिता दोनों धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं;
 - (ख) कोई वैध या अवैध बच्चा, जिसके माता-पिता में से एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है और जिसका पालन-पोषण उस जनजाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया है जिससे ऐसे माता-पिता संबंधित हैं या संबंधित हैं; और
 - (ग) कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित या फिर से परिवर्तित हो गया है।
- (2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम में निहित कुछ भी संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्यथा निर्देश नहीं देती है।
- (3) इस अधिनियम के किसी भी भाग में "हिंदू" पद का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा जैसे कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो धर्म से हिंदू नहीं है, फिर भी, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए यह अधिनियम इस धारा में निहित प्रावधानों के आधार पर लागू होता है।

बच्चा 1976 के अधिनियम 68 के प्रारंभ से पहले या बाद में पैदा हुआ है जो धारा 16 के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है और क्या

(i) विवाह के संबंध में निरर्थकता की डिक्री दी गई थी; और (ii) विवाह को अधिनियम के अंतर्गत एक याचिका के अलावा अन्यथा शून्य माना गया था।

15. उप-धारा (1) के विपरीत, उप-धारा (2) वैधता के एक मानित परिणाम को मूर्त रूप देती है, जो धारा 12 के अंतर्गत शून्यता की डिक्री पर निर्भर करती है, जहां डिक्री बनाए जाने से पहले बच्चे को "जन्म या गर्भधारण" किया जाता है, अगर बच्चा विवाह के पक्षों का वैध बच्चा होता, अगर उसे डिक्री की तारीख को रद्द किए जाने के बजाय भंग कर दिया जाता। एक बार उप-धारा (1) और (2) की शर्तों को पूरा करने के बाद, दोनों प्रावधान अनिवार्य रूप से बच्चे की वैधता की रक्षा करते हैं।

ग. माता-पिता की संपत्ति में या उसके अधिकार

16. धारा 16 की उप-धारा (3) एक गैर-अस्थायी प्रावधान ("उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निहित कुछ भी नहीं") के साथ शुरू होती है। संसद उप-धारा (3) को अधिनियमित करते समय यह सुनिश्चित करने का इरादा रखती है कि वैधता का विधायी सम्मान, "माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति में कोई अधिकार", एक शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए ऐसे बच्चे को प्रदान नहीं करेगा, लेकिन कानून पारित करने के लिए, बच्चा माता-पिता की वैध संतान नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता। उप-धारा (3) में दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं: पहला है "माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके लिए कोई अधिकार"; और दूसरा है "जहां इस अधिनियम को पारित करने के लिए ऐसा बच्चा अपने माता-पिता की वैध संतान नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता"। उप-धारा (3), दूसरे शब्दों में, संपत्ति में अधिकारों के प्रदान करने के संबंध में बच्चे की वैधता के विधायी संरक्षण के परिणाम को सीमित करती है। लेकिन उप-धारा (3) के लिए, एक अमान्य या अमान्य विवाह से एक बच्चे को वैधता प्रदान करने से बच्चे को, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, संपत्ति से संबंधित मामलों में एक वैध बच्चे के बराबर रखा जाता। हालाँकि, उप-धारा (3) की रूपरेखा इंगित करती है कि वैधता प्रदान करने से माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके लिए बाल अधिकार प्रदान नहीं होंगे। उप-धारा (3) स्पष्ट रूप से मान्यता देती है कि बच्चे को 337 से सम्मानित किया गया है।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 338

उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों के आधार पर वैधता के साथ बच्चे के माता-पिता की संपत्ति में या उसके अधिकारों का हकदार होगा। लेकिन प्रावधान समान रूप से इंगित करता

है कि वैधता प्रदान करना उन व्यक्तियों की संपत्ति में या उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए काम नहीं करेगा जो बच्चे के माता-पिता नहीं हैं। हालाँकि, यह शर्त उप-धारा (3) के अंतिम भाग द्वारा सशर्त है जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति में या उस पर अधिकार नहीं होंगे जो माता-पिता नहीं है, लेकिन अधिनियम के पारित होने के लिए बच्चा वैध बच्चा नहीं होने के कारण ऐसे अधिकारों को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता। उप-धारा (3) का यह अंतिम भाग हमें उस स्थिति में वापस ले जाता है जो अधिनियम के पारित होने से पहले थी। यदि, लेकिन प्रावधान के अधिनियमन के लिए बच्चा 'अवैधता' के आधार पर माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार रखने या प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता, तो बच्चे को किसी तीसरे पक्ष (माता-पिता के अलावा) की संपत्ति पर या उसमें अधिकार नहीं होंगे। अपने स्पष्ट शब्दों से, धारा 16 (3) इंगित करती है कि संसद, एक अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैधता प्रदान करते हुए, माता-पिता और माता-पिता के अलावा किसी अन्य पक्ष की संपत्ति में बच्चे के अधिकारों को स्वीकार करती है।

D. संदर्भ में मुद्दे

17. संदर्भ अनिवार्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे को उठाता है: क्या कोई बच्चा जिसे धारा 16 (1) या 16 (2) के अंतर्गत विधायी वैधता प्रदान की गई है, धारा 16 (3) के कारण माता-पिता की पैतृक/सह-आंशिक संपत्ति का हकदार है या बच्चा केवल माता-पिता की स्व-अर्जित/अलग संपत्ति का हकदार है। हमारे सामने जो प्रश्न उठते हैं वे हैं-पहले, क्या विधायी इरादा धारा 16 द्वारा कवर किए गए बच्चे को इस तरह से वैधता प्रदान करना है जो उन्हें सह-भागीदार बनाता है, और इस प्रकार विभाजन में शुरुआत करने या हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है-वास्तविक या काल्पनिक; दूसरा, किस बिंदु पर एक विशिष्ट सी संपत्ति माता-पिता की संपत्ति बनने में परिवर्तित होती है। क्योंकि, यह केवल ऐसी संपत्ति के भीतर है कि विधायी वैधता से संपन्न बच्चे धारा 16 (3) के अनुसार हकदार हैं। 18. बाद के प्रश्न का उत्तर मुख्य रूप से 'माता-पिता के अलावा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में या उसके किसी भी अधिकार' वाक्यांश की व्याख्या पर निर्भर करेगा। वाक्यांश के दायरे और अधिकार के दायरे को समझने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाएगा।

/

[2023] 14 एस सी आर।

19. इस स्तर पर, हिंदू अविभाजित परिवार की संस्था में अंतर्निहित बुनियादी उपदेशों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बाद में, उन उपदेशों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद, निर्णय का ध्यान उस तरीके पर केंद्रित होगा जिसमें एच. एस. ए. 1956 ने (i) सह-आंशिक संपत्ति में

ब्याज के हस्तांतरण को विनियमित किया है; (ii) उत्तराधिकार के सामान्य नियम निर्धारित किए हैं; और (iii) संपत्ति के वितरण के लिए निर्धारित सिद्धांत।

ई. प्रस्तुतियाँ

20. संदर्भ और ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, अब हम धारा 16 (3) की व्याख्या और वैधता प्रदान करने के पीछे के विधायी इरादे के संबंध में प्रस्तुतियों को टाल देंगे।

प्रथम, अधिक विस्तृत, सूत्रीकरण को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: i) माता-पिता की संपत्ति में सह-सहभागी संपत्ति का हिस्सा शामिल है-एक बार जब बड़ी सह-सहभागी (पिता और उसके पिता, भाइयों आदि सहित) का विभाजन हो जाता है, तो संपत्ति को पिता और उसके सभी बच्चों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें धारा 16 द्वारा कवर किए गए बच्चे भी शामिल हैं। (ii) यह प्रावधान बच्चों को वैधता के सभी अर्थ प्रदान करता है-जिसमें पिता की संपत्ति में सह-पक्षीय अधिकार भी शामिल हैं।

दूसरी ओर, दूसरे सूत्रीकरण के अनुसार (i) विभाजन के बाद पिता के हाथों में बड़ी सह-संपत्ति से संपत्ति, अभी भी पिता के साथ-साथ बच्चों (जिन्हें स्वयं वैध माना जाता है) की सह-संपत्ति है; इस प्रकार, यह धारा 16 (3), एच. एम. ए. के अनुसार 'माता-पिता की संपत्ति' नहीं है और इस प्रकार, धारा 16 (3) के अंतर्गत बच्चों को इसमें कोई अधिकार नहीं है। (ii) विधायिका का इरादा केवल कलंक को मिटाना था, और एक सह-सदस्य की संरचना में हस्तक्षेप नहीं करना था जिसमें धारा 16 द्वारा कवर किए गए बच्चे शामिल नहीं हैं; और (iii) इस प्रकार, धारा 16 (3) के अंतर्गत, माता-पिता की स्व-अर्जित/स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में एकमात्र अधिकार है।

अधिक विस्तृत व्याख्या को निम्नलिखित सूत्रीकरणों के आधार पर प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है:

ए। एच. एस. ए. 1956 की धारा 16 (3) के अंतर्गत वैधता वाले बच्चों को पिता की शाखा के भीतर विभाजन के उद्देश्य के लिए वैध माना जाना चाहिए। वे विभाजन 339 का दावा नहीं कर सकते।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 340

वृहद समभागीदारी में, लेकिन एक बार जब वृहद समभागीदारी का विभाजन हो जाता है-वैचारिक रूप से या वास्तव में, और संपत्ति पिता के हाथों में आ जाती है, तो उसके सभी बच्चों को-धारा 16 (3) के कारण वैध या वैध, इस संपत्ति को पिता के हाथों में विभाजित करने में समान अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में, एक वैध बच्चे और धारा 16 (3) के अंतर्गत वैधता से सम्मानित बच्चे के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पिता की मृत्यु के बाद, बाद वाला

बड़े सह-पक्ष में विभाजन का दावा नहीं कर सकता है, उन बच्चों के विपरीत जो स्वयं वैध हैं। उनके अधिकार पर यह सीमा तब समाप्त हो जाती है जब बड़े सह-सदस्य में पिता का हिस्सा निर्धारित हो जाता है। पिता के हिस्से में-एक बार निर्धारित और बड़े सह-सदस्य से अलग होने के बाद, उन्हें वैध बच्चों के समान अधिकार हैं।

बी। संशोधन का उद्देश्य केवल अमान्य या अमान्य विवाहों के बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाले कलंक को समाप्त करना नहीं है, बल्कि सभी वैध बच्चों के साथ समान व्यवहार करना है। यह कानूनी निर्णय का तार्किक परिणाम है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक बार जब एक कानूनी अधिकार बनाया जाता है, जैसा कि धारा 16 (3) द्वारा बनाया गया है, तो सह-आंशिक संपत्ति में अधिकारों सहित इसके सभी अपरिहार्य परिणाम भी मान लिए जाते हैं।

ग. धारा 16 (3) पैतृक/सह-स्वामित्व या अलग/स्व-अर्जित के साथ "संपत्ति" शब्द को योग्य नहीं बनाती है। इसलिए, माता-पिता की सह-आंशिक संपत्ति को बाहर करने के लिए इस तरह की योग्यता दर्ज करना न्यायालय द्वारा कानून होगा। अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए ऐसे बच्चों को सह-संपत्ति सहित माता-पिता की संपत्ति के अधिकार से वंचित करना अनुचित रूप से कठोर है।

16 अपीलार्थी की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ रेवनसिदप्पा और अन्न बनाम मल्लिकार्जुन और अन्य किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पृष्ठ 3-4

17 श्री सुधांशु चौधरी द्वारा बालकृष्ण पांडुरंग हल्दे बनाम यशोदाबाई बालकृष्ण हल्दे में याचिकाकर्ताओं की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ, पृष्ठ 2, पैरा 3

18 श्री सुधांशु चौधरी द्वारा बालकृष्ण पांडुरंग हल्दे बनाम यशोदाबाई बालकृष्ण हल्दे में याचिकाकर्ताओं की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ, पृष्ठ 7, पैरा 2

19 डॉ. रवींद्र चिंगले द्वारा रेवनसिदप्पा बनाम मल्लिकार्जुन में अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत लिखित टिप्पणी, पृष्ठ 2

/

[2023] 14 एस सी आर।

घ. 1976 के अधिनियम 68 का विधायी उद्देश्य सभी वैध बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना है। एक बार जब अमान्य और अमान्य विवाहों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है, तो उनके और वैध विवाहों से पैदा हुए अन्य वैध बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता है।²¹

ई. एच. एस. ए. 1956 की धारा 2 धारा 6 सहित अधिनियम को शून्य/अमान्य विवाहों से पैदा हुए बच्चों पर लागू करती है, जो सह-संपत्ति से संबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 नियम 1 अमान्य या अमान्य विवाहों से पैदा हुए उत्तराधिकारियों और कानूनी विवाह से पैदा हुए उत्तराधिकारियों के बीच अंतर नहीं करती है। इसी तरह प्रथम श्रेणी के

उत्तराधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत वैधता के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है। निहित रूप से, समग्र रूप से विधि, सभी उद्देश्यों के लिए, जिसमें काल्पनिक और वास्तविक विभाजन भी शामिल है, माता-पिता की सह-आंशिक संपत्ति में और उसके अधिकारों सहित सभी उद्देश्यों के लिए वैध बच्चों के बीच अलग-अलग व्यवहार का इरादा नहीं रखता है। वैधता से सम्मानित बच्चे को इस तरह के अधिकार का हकदार होने के लिए सह-भागीदार होने की आवश्यकता नहीं है।

च. धारा 16 (3) के उत्तरार्द्ध भाग में कहा गया है-"कहाँ लेकिन पारित करने के लिए।

इस अधिनियम के तहत, ऐसा बच्चा वैध नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता।

अपने माता-पिता की संतान। धारा 4 अधिनियम के प्रावधानों को उनके तहत विशिष्ट रूप से शामिल मामलों में एक प्रमुख प्रभाव प्रदान करती है। यह अधिनियम "सह-विभाजन" की अवहेलना नहीं करता है। इसलिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से पहले विधि की स्थिति "सह-पक्ष" के संबंध में लागू होती है। विधि अंतर्गत जैसा कि तब था, वैधता की परवाह किए बिना, एक ही पुरुष पूर्वज से पैदा हुए सभी बच्चों को सह-भागीदार माना जाता था।²³

20 श्री सुधांशु चौधरी द्वारा बालकृष्ण पांडुरंग हल्दे बनाम यशोदाबाई बालकृष्ण हल्दे में याचिकाकर्ताओं की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ, पृष्ठ 7, पैरा 3

21 श्री ए. आई. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पृष्ठ 8 द्वारा मनकरनबाई बनाम निरंजन में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रत्युत्तर में तर्कों के संक्षिप्त नोट।

22 श्री में श्री निखिल मजीठिया की लिखित प्रस्तुतियाँ। ईश्वरचारी बनाम श्रीमती। सरोजम्मा, पृष्ठ 4।

23 श्री में श्री निखिल मजीठिया की लिखित प्रस्तुतियाँ। ईश्वरचारी बनाम श्रीमती। सरोजम्मा, पृष्ठ 4-5।

341

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओ. आर. एस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 342

छ. धारा 16 (3) का सीमित अध्ययन भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है।

उपरोक्त व्याख्या पर निम्नलिखित सूत्रीकरणों के आधार पर सवाल उठाया गया है:

ए। एक बच्चे को वैधता प्रदान करने और उन्हें सह-भागीदार का दर्जा देने के बीच एक अंतर है। जबकि एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 वैधता प्रदान करती है, धारा 16 (3) उत्तराधिकार अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करती है।²⁵ यह अंतर जिनिया के ओटिन में निर्णय के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है, जहां न्यायालय ने माना कि धारा 16 (3) के तहत आने वाले बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति तक सीमित अधिकार हैं।²⁶

बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 एक बोधगम्य भिन्नता के साथ उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, जो विभिन्न विवाहों के बच्चों के साथ विशिष्ट कानूनी स्थिति के कारण अलग-अलग व्यवहार को उचित ठहराता है। यह वर्गीकरण एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए वैध ऑफ स्प्रिंग और निर्दोष सह-भागीदारों दोनों के हितों की रक्षा करता है।-

ग. धारा 16 के पीछे विधायी उद्देश्य अमान्य और अमान्य विवाहों से बच्चों को वैधता और विरासत के अधिकार प्रदान करना है। हालाँकि, ये अधिकार जानबूझकर माता-पिता की संपत्ति तक सीमित हैं, जिसमें सह-स्वामित्व या पैतृक संपत्ति शामिल नहीं है, जैसा कि विधायी इतिहास और उद्देश्यों से पता चलता है।²⁸

24 श्री सुधांशु चौधरी द्वारा बालकृष्ण पांडुरंग हल्दे बनाम यशोदाबाई बालकृष्ण हल्दे में याचिकाकर्ताओं की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ, पृष्ठ 8

25 उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राधाकृष्णन ने रेवनसिदप्पा और अन्न बनाम मल्लिकार्जुन और अन्य, 2011 की सी. ए. संख्या 2844 में प्रस्तुत किया।

26 बेबी @रोहिणी (मृतक होने के बाद से) में उत्तरदाताओं की ओर से श्री पी. बी. सुरेश द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों और अन्य बनाम कमलम कुमारेसन और अन्य, 2016 के एसएलपी® 14176-14177 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया

27 उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राधाकृष्णन ने रेवनसिदप्पा और अन्न बनाम मल्लिकार्जुन और अन्य, 2011 की सी. ए. संख्या 2844 में प्रस्तुत किया।

28 बेबी @रोहिणी (मृतक होने के बाद से) में उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती वी. मोहना द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों और अन्य बनाम कमलम कुमारसन और अन्य, 2016 के एसएलपी® 14176-14177 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया

/

[2023] 14 एस सी आर।

घ. विधायिका ने वैध बच्चों के विरासत के अधिकारों को संबोधित करने के लिए कई बार हस्तक्षेप किया है:

आई. प्रारंभिक एच. एम. ए. प्रावधान (धारा 16): हिंदू विवाह अधिनियम (एच. एम. ए.) के अधिनियमन में धारा 16 शामिल थी, जिसमें अमान्य या अमान्य विवाह से बच्चों को उनके माता-पिता के वैध बच्चों के रूप में स्थापित किया गया था।

ii. 1976 धारा 16 में संशोधन: 1976 में एच. एम. ए. की धारा 16 में भेदभाव पैदा करने वाले मुद्दों को सुधारने के लिए संशोधन किया गया था। iii. एचएसए संशोधन (धारा 6 (3)): हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (एच. एस. ए.) की धारा 6 में संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 6 (3) को लागू किया गया था जो सह-संपत्ति में माता-पिता के अविभाजित हित के काल्पनिक विभाजन को लागू करता है।²⁹

इस प्रकार, जहां तक अमान्य या अमान्य विवाहों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों का संबंध है, कोई विधायी शून्य नहीं है। इस प्रकार, ऐसे बच्चों के अधिकारों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

ई. विभिन्न संशोधनों के माध्यम से, संसद ने यह सुनिश्चित किया है कि इन बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति के दायरे में विरासत के अधिकार प्राप्त हों।³⁰ इस प्रक्रिया ने विरासत में मिली संपत्ति को माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में बदल दिया है, जिससे वैध बच्चे एच. एम. ए. की धारा 16 में उल्लिखित लाभों का उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं। ऐसे उदाहरणों में, संसद के हस्तक्षेपों का उद्देश्य सार्वजनिक नीति के विकसित विचारों के साथ मिताक्षर विधि का मिलान करना था, जिससे इन बच्चों और अन्य भागीदारों के हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाया जा सके।³¹

29 बेबी @रोहिणी (मृत होने के बाद से) में प्रतिवादी संख्या 71 और 81 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक चिब द्वारा उनके कानूनी प्रतिनिधियों और ओआरएस बनाम कमलम कुमारेसन और ओआरएस, एसएलपी (सी) संख्या 2016 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

30 बेबी @रोहिणी (मृत होने के बाद से) में उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती वी. मोहना द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों और अन्य बनाम कमलम कुमारेसन और अन्य, 2016 के एसएलपी® 14176-14177 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया

31 बेबी @रोहिणी (मृत होने के बाद से) में प्रतिवादी संख्या 71 और 81 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक चिब द्वारा उनके कानूनी प्रतिनिधियों और ओआरएस बनाम कमलम कुमारेसन और ओआरएस, 2016 343 की एसएलपी (सी) संख्या 14176-14177 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 344

च. 1976 के संशोधन का उद्देश्य धारा 16 के अंतर्गत विरासत अधिकारों के सीमित दायरे को स्पष्ट और सुदृढ़ करना था।³² इसका उदाहरण अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ³³ में निर्णय द्वारा दिया गया है, जो दर्शाता है कि कैसे विधायी कार्य और संशोधन लगातार संभावित विधि की रिक्तियों को संबोधित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी वैध बच्चों के विरासत अधिकारों से संबंधित विधि में कोई अंतराल नहीं है।

एफ. संयुक्त हिंदू अंतर्गत विवार और मिताक्षर के अधीन सह-सदस्य

21. परंपरागत रूप से, एक संयुक्त हिंदू परिवार में पुरुष सदस्य होते हैं जो अपनी माताओं, पत्नियों या विधवाओं और अविवाहित बेटियों के साथ एक सामान्य पुरुष पूर्वज के वंशज होते हैं। एक संयुक्त हिंदू परिवार को 'एक बड़े निकाय' के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें व्यक्तियों का एक समूह होता है जो सपिंडाशिप या पारिवारिक संबंधों से एकजुट होता है।

22. एक हिंदू सह-प्रतिनिधि में एक प्रस्तावक और तीन वंशजों के वंशज होते हैं। एक हिंदू सह-सदस्य एक ऐसा निकाय है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार की तुलना में संकीर्ण है।

2005 से पहले, इसमें केवल बेटे, पोते और परपोते शामिल थे जो संयुक्त संपत्ति के धारक थे।
35 (विनीता शर्मा बनाम राकेश

शर्मा **36** ("विनीता शर्मा")।**23.** भारतीय स्टेट बैंक बनाम घमंडीराम **37** ("घमंडीराम") में,

इस न्यायालय ने कहा कि हिंदू विधि के मिताक्षर स्कूल के अंतर्गत , सभी

32 हनुमंत नामदेव जाधव और अन्य बनाम काशीबाई नामदेव जाधव और अन्य, 2017 की एसएलपी (सी) संख्या 27834 में प्रत्यर्थियों की ओर से रिकॉर्ड पर अधिवक्ता श्री सम्राट के शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया

33 (2020) 13 एस. सी. सी. 585

34 सुनील कुमार बनाम राम प्रकाश:(1988) 2 एस. सी. सी. 77; श्रीमती सीताबाई बनाम रामचंद्र:(1969) 2 एस. सी. सी. 544; गौली बुद्धना बनाम सी. आई. टी., मैसूर, बैंगलोर:ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1523; सुरजित लाल छाबड़ा बनाम आयकर आयुक्त बॉम्बे:(1976) 3 एस. सी. सी. 142

35 "23. हिंदू सह-पक्ष एक बहुत संकीर्ण शरीर है। इसमें प्रस्तावक और तीन वंशावली वंशज शामिल हैं। 2005 से पहले, इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल थे जैसे बेटे, पोते और परपोते जो संयुक्त संपत्ति के धारक हैं। उदाहरण के लिए, यदि ए के पास संपत्ति है, तो बी उसका बेटा है, सी उसका पोता है, डी परपोता है, और ई एक परपोता है। सहसदस्यता का गठन डी अर्थात् प्रपौत्रों तक किया जाएगा, और केवल संपत्ति के धारक ए की मृत्यु पर, ई का अधिकार सहसदस्यता में पक जाएगा क्योंकि सहसदस्यता तीन वंशजों को दी जाती है। चूंकि पोते और परपोते जन्म से सह-भागीदार बन जाते हैं, इसलिए उन्होंने संपत्ति में रुचि हासिल कर ली। "

36 (2020) 9 एससीसी 1

37 (1969) 2 एससीसी 33

/

[2023] 14 एस सी आर।

एक हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति सभी सह-भागीदारों द्वारा "अर्ध-निगमित क्षमता" में सामूहिक स्वामित्व में रखी जाती है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सहसदस्यता की घटनाएं इस प्रकार हैं:

(i) किसी व्यक्ति के तीसरी पीढ़ी तक के वंशानुगत पुरुष वंशज ऐसे व्यक्ति की पैतृक संपत्तियों में जन्म स्वामित्व प्राप्त करते हैं।

((ख) ऐसे वंशज किसी भी समय विभाजन की मांग करके अपने अधिकारों का निर्धारण कर सकते हैं।

((ग) विभाजन तक, समभागीदारी के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व शेष के साथ संयुक्त रूप से पूरी संपत्ति पर फैला हुआ है।

((iv) इस तरह के सह-स्वामित्व का परिणाम यह है कि संपत्तियों का कब्जा और आनंद सामान्य है।

(v) संपत्ति का कोई अलगाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि यह सह-भागीदारों की सहमति के बिना आवश्यकता के लिए न हो; और

(vi) मृतक सदस्य की सह-सदस्यता में रुचि उसकी मृत्यु पर उसके जीवित बचे लोगों के पक्ष में समाप्त हो जाती है।

24. एक सह-सदस्य की विशेषता यह है कि तीसरी पीढ़ी तक का एक वंशानुगत पुरुष जन्म से स्वामित्व का एक स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करेगा और एक मृत सदस्य का हित उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा और सह-सदस्य संपत्ति में विलय हो जाएगा। सह-अधिवेशन के सदस्य को विभाजन की मांग करने का अधिकार है। विभाजन तक, संपत्ति संयुक्त रूप से सभी के स्वामित्व में होती है, और व्यक्तिगत शेयरों को सह-भागीदारों द्वारा अनुमानित नहीं किया जा सकता है। घमंडीराम (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांतों का विश्लेषण और उन्हें तैयार किया गया था

संपत्ति शुल्क नियंत्रक, मद्रास बनाम अल्लादी कुप्पुस्वामी **38**, जहां

न्यायालय ने कहा: “33. ... एक हिंदू सह-सदस्य की छह आवश्यक विशेषताएं हैं, अर्थात् (1) तीसरी पीढ़ी तक के वंशानुगत पुरुष वंशज जन्म से स्वामित्व का एक स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करते हैं न कि अपने पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हुए; (2) सह-सदस्य के सदस्यों को विभाजन की मांग करके अपने अधिकारों को पूरा करने का अधिकार है; (3) विभाजन तक,

38 (1977) 3 एससीसी 385 345

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 346

प्रत्येक सदस्य को शेष के साथ संयुक्त रूप से पूरी संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त है और जब तक कोई विभाजन नहीं होता है, तब तक किसी भी सह-भागीदार के लिए उस हिस्से का अनुमान लगाना मुश्किल है जो वह प्राप्त कर सकता है; (4) कि इस तरह के सह-स्वामित्व के परिणामस्वरूप संपत्ति का कब्जा और आनंद सामान्य है; (5) कि अन्य सह-भागीदारों की सहमति के बिना संपत्ति का कोई अलगाव नहीं हो सकता है जब तक कि यह कानूनी आवश्यकता के लिए न हो; और (6) कि किसी मृत सदस्य का हित उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है और सह-आंशिक संपत्ति में विलय हो जाता है। ”

25. महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम राव देशमुख 39,

इस न्यायालय ने दोहराते हुए कहा कि एक हिंदू सह-सदस्य एक संयुक्त परिवार की तुलना में एक संकीर्ण निकाय है।

“40... “ ७ ...केवल वे पुरुष जो जन्म से संयुक्त या सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज प्राप्त करते हैं, वे सह-पक्षीय या सह-पक्षकारों के सदस्य हो सकते हैं। एक संयुक्त परिवार का एक पुरुष सदस्य और उसके बेटे, पोते और महान पोते एक सह-सदस्य होते हैं। एक सह-भागीदार प्राप्त करता है

जन्म से सह-स्वामित्व वाली संपत्ति में अधिकार लेकिन उसके अधिकार का निश्चित रूप से तभी पता लगाया जा सकता है जब विभाजन होता है। जब परिवार संयुक्त होता है, तो एक सह-भागीदार के हिस्से की सीमा को निश्चित रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह हमेशा फूलने में सक्षम होता है। यह एक सह-भागीदार की मृत्यु से बढ़ता है और एक सह-भागीदार के जन्म पर कम हो जाता है। एक संयुक्त परिवार,

हालाँकि, इसमें महिला सदस्य शामिल हो सकती हैं। इसमें एक पुरुष सदस्य, उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी अविवाहित बेटियाँ शामिल हो सकती हैं। "

न्यायालय ने कहा कि एक संयुक्त परिवार की संपत्ति केवल इसलिए परिवार से संबंधित नहीं रह जाती है क्योंकि परिवार में केवल एक पुरुष सदस्य बचा है। न्यायालय ने मिताक्षर हिंदू विधि और दयाभाग विधि में स्थिति के बीच के अंतर पर विस्तार से टिप्पणी करते हुए कहा:

“40...

8...

जबकि मिताक्षर हिंदू विधि के अंतर्गत सभी के साथ संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के स्वामित्व और स्वामित्व की एकता का समुदाय है।

39 (1985) 2 एस. सी. सी. 321

/

[2023] 14 एस सी आर।

सहसदस्यता के सदस्य, दयाभाग विधि द्वारा शासित सहसदस्यता में, सहसदस्यता संपत्ति के स्वामित्व की उसके सदस्यों के साथ कोई एकता नहीं है। प्रत्येक सह-भागीदार संपत्ति में एक निश्चित हिस्सा लेता है और वह उस हिस्से का मालिक होता है। लेकिन, हालाँकि, अधिकार की एकता है। यह हिस्सा जन्म और मृत्यु से कम नहीं होता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि डेफी नाइट शेयर के अधिकार की मान्यता दयाभाग विधि में संपत्ति के मालिकों को एक परिवार से संबंधित माने जाने के खिलाफ नहीं है। "

मिताक्षर विधि की स्थापना एक ऐसे हित के समुदाय पर की गई है जिसमें कहा गया है कि सह-पक्षीय संपत्ति का स्वामित्व सह-पक्षकारों के पूरे निकाय में संयुक्त रूप से निहित है। सह-सदस्य के सदस्य का हित एक उत्साहवर्धक ब्याज है, जो मृत्यु द्वारा बढ़ाया जा सकता है और परिवार में जन्म द्वारा कम किया जा सकता है। विभाजन पर, हालाँकि, सह-भागीदार का

हिस्सा स्पष्ट हो जाता है, और वे एक निश्चित रात के हिस्से के हकदार हो जाते हैं। इन सिद्धांतों को वेल्लिकन्नू बनाम आर. सिंगापेरुमल 40 और रोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह 41 में दोहराया गया है। एक सह-भागीदार के हित को उस अर्थ में 'एक अविभाजित सह-भागीदार' के रूप में संदर्भित किया जाता है (इस संदर्भ में, कटमा नचियर बनाम शिवगंगा 42 के राजा में प्रिवी काउंसिल का निर्णय देखें)। विनीता शर्मा (ऊपर) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय इस विषय पर उदाहरणों का व्यापक रूप से विश्लेषण करता है।

G. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

26. एच. एस. ए. 1956 की धारा 6 मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज के हस्तांतरण का प्रावधान करती है। 2005 के अधिनियम 39 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले, धारा 6 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे: “6. सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण।- जब इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है, जिसकी मृत्यु के समय किसी मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज होता है, तो संपत्ति में उसका हित सह-आंशिक के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि इस अधिनियम के अनुसार:

40 (2005) 6 एससीसी 622 41 (2013) 9 एससीसी 419

42 1863 एससीसी ऑनलाइन पीसी 11 347

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 348

बशर्ते कि, यदि मृतक ने अनुसूची के प्रथम वर्ग में विनिर्दिष्ट महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में विनिर्दिष्ट पुरुष रिश्तेदार को जीवित छोड़ दिया था, जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, तो मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के अंतर्गत वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

स्पष्टीकरण 1.— इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से तुरंत पहले हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

स्पष्टीकरण 2.— इस धारा के परंतुक में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह व्यक्ति जिसने मृतक की मृत्यु से पहले सहसदस्यता से खुद को अलग कर लिया है या उसके किसी भी उत्तराधिकारी को निर्वसीयता पर उसमें निर्दिष्ट ब्याज में एक हिस्से का दावा करने में सक्षम बनाता है। ”

27. धारा 6, जैसा कि संशोधन से पहले था, में प्रावधान किया गया था कि एक पुरुष हिंदू का सह-आंशिक हित, जिसकी अधिनियम के प्रारंभ के बाद मृत्यु हो गई थी, उत्तरजीवी द्वारा

हस्तांतरित किया जाएगा। धारा 6, दूसरे शब्दों में, उत्तरजीविता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से शामिल करके वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को बाहर कर दिया। धारा 6 के परंतुक में हालांकि एक अपवाद शामिल था जहां मृतक ने अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट महिला रिश्तेदार या वर्ग के एक पुरुष रिश्तेदार को जीवित छोड़ दिया था, जिसने ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा किया था, जिस मामले में मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में मृतक का हित अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के वसीयती या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा विभाजित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा। धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 में एक ऐसा निर्णय था जिसके अनुसार धारा के प्रयोजन के लिए, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाता था जो उसे आवंटित किया जाता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति का विभाजन हुआ होता।

28. धारा 6 के प्रावधान, जैसा कि वे संशोधन से पहले थे, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आए।

गुरुपद खंडप्पा बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदुम **43**. उस मामले में,

43 (1978) 3 एस. सी. सी. 383

/

[2023] 14 एस सी आर।

मिताक्षरा सह-स्वामित्व संपत्ति में रुचि रखने वाले खंडप्पा की 27 जून 1960 को मृत्यु हो गई और वे अपनी पत्नी हीराबाई, अपने दो बेटों और तीन बेटियों को छोड़ गए। हीराबाई ने विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया। चूंकि विधवा और बेटियाँ अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट पारिवारिक रिश्तेदारों में से थीं, इसलिए धारा 6 का प्रावधान लागू हुआ और उत्तरजीविता के सामान्य नियम को बाहर रखा गया। इस न्यायालय ने नोट किया कि वादी की राहत दो चीजों द्वारा निर्धारित की गई थी: (i) अपने पति के हिस्से में उसका हिस्सा; और (ii) सह-आंशिक संपत्ति में उसके पति का अपना हिस्सा। चूंकि मृतक के परिवार में दो बेटे, तीन बेटियाँ और उसकी विधवा थी, इसलिए न्यायालय ने कहा कि छह भागीदारों में से प्रत्येक का 1/6 का बराबर हिस्सा होगा। अगला कदम यह निर्धारित करना था कि मृतक का सह-आंशिक संपत्ति में कितना हिस्सा था। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने कहा:

“9. अगला कदम, समान रूप से महत्वपूर्ण है, हालांकि इसे निकालना समान रूप से आसान नहीं है, वह है उस हिस्से को निकालना जो मृतक के पास सह-आंशिक संपत्ति में था क्योंकि आखिरकार, वादी का उस हिस्से में छठा हिस्सा है। स्पष्टीकरण 1, जिसमें मृतक के हिस्से का निर्धारण करने का सूत्र है, यह उपबंध करते हुए एक निर्णय बनाता है कि किसी हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार का हित उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति का विभाजन हुआ होता। इसलिए, किसी

को ऐसी स्थिति की कल्पना करनी चाहिए जिसमें खंडप्पा की मृत्यु से कुछ समय पहले, उनके और सह-सदस्य के अन्य सदस्यों के बीच सह-सदस्य संपत्ति का विभाजन किया गया था। यद्यपि वादी, सह-भागीदार नहीं होने के कारण, विभाजन की मांग करने का हकदार नहीं था, फिर भी यदि उसके पति और उसके दो बेटों के बीच विभाजन होता है तो वह एक बेटे के बराबर हिस्सा प्राप्त करने की हकदार होगी। (मुल्ला का हिंदू विधि, 14 वीं संस्करण देखें। 403, पैरा 315)। खंडप्पा और उनके दो बेटों के बीच एक विभाजन में सह-पक्षीय संपत्ति में चार हिस्सेदार होंगे-चौथा खंडप्पा की पत्नी, वादी होगी। इसलिए खंडप्पा को अपने और अपने बेटों के बीच विभाजन की परिकल्पना पर सह-आंशिक संपत्ति में एक चौथाई हिस्सा मिला होगा। "

उनके, उनकी विधवा और उनके 2 बेटों के बीच सह-आंशिक संपत्ति के एक काल्पनिक विभाजन में, खंडप्पा ने 1/4 वां हिस्सा प्राप्त किया होगा। वादी का अपने 1/4 वें हिस्से में हिस्सा 1/6 वां, यानी 1/24 th था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी के हिस्से को 349 तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 350

अगर उनके पति के जीवनकाल के दौरान उनके और उनके दो बेटों के बीच वास्तविक विभाजन होता तो उन्हें प्राप्त होने वाले 1/4 वें हिस्से की अनदेखी की जाती। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 6 का स्पष्टीकरण "इस धारणा को बाध्य करता है कि वास्तव में संपत्ति का विभाजन उस व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले हुआ था जिसकी संपत्ति में उत्तराधिकारियों ने हिस्सेदारी का दावा किया था। इस न्यायालय ने कहा:

“13. मृतक सह-भागीदार की संपत्ति में उत्तराधिकारियों के हिस्से का पता लगाने के लिए चीजों की प्रकृति में और पहले कदम के रूप में, सह-सहभागी संपत्ति में मृतक के हिस्से का पता लगाना आवश्यक है। क्योंकि, ऐसा करने से ही दावेदार के हिस्से की सीमा निर्धारित की जा सकती है। धारा 6 का स्पष्टीकरण 1 सरल समीचीन, निस्संदेह वितीय का सहारा लेता है, कि एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता यदि उस संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता। इसलिए यह मान लेना आवश्यक है कि वास्तव में मृतक और उसके सह-भागीदारों के बीच उनकी मृत्यु से ठीक पहले एक विभाजन हुआ था। यह धारणा, एक बार की गई, अपरिवर्तनीय है। दूसरे शब्दों में, यह धारणा सह-आंशिक संपत्ति में मृतक के हिस्से का पता लगाने के उद्देश्य से एक बार की गई है, कोई भी उस धारणा पर वापस नहीं जा सकता है और इसके संदर्भ के बिना उत्तराधिकारियों के हिस्से का पता नहीं लगा सकता है। यह धारणा कि कानून के अनुसार विभाजन वास्तव में हुआ था, सभी चरणों में उत्तराधिकारियों के अंतिम हिस्से का पता लगाने की पूरी प्रक्रिया में व्याप्त होनी चाहिए। मृतक के हिस्से का पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रारंभिक चरण में धारणा बनाना और फिर उत्तराधिकारियों

के हिस्से की मात्रा की गणना के लिए इसे अनदेखा करना वास्तव में किसी की कल्पना को भ्रमित करने की अनुमति देना है। वास्तविक विभाजन से होने वाले सभी परिणामों को तार्किक रूप से निर्धारित करना होगा, जिसका अर्थ है कि उत्तराधिकारियों के हिस्से का निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे एक दूसरे से अलग हो गए थे और विभाजन में एक हिस्सा प्राप्त किया था जो मृतक के जीवनकाल के दौरान हुआ था। इस हिस्से का आवंटन केवल किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक प्रक्रियात्मक कदम नहीं है। इसे एक ठोस वास्तविकता के रूप में माना और स्वीकार किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे केवल एक वास्तविक विभाजन में एक सह-भागीदार को आवंटित हिस्से के रूप में याद नहीं किया जा सकता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

आम तौर पर याद किया जाता है। इस स्थिति का अपरिहार्य परिणाम यह है कि उत्तराधिकारी को उस हिस्से के अलावा उस ब्याज में अपना हिस्सा मिलेगा जो मृतक की मृत्यु के समय सह-आंशिक संपत्ति में था, जो उसे काल्पनिक विभाजन में प्राप्त हुआ था या माना जाना चाहिए था। "

29. "महिलाओं के संपत्ति अधिकार" शीर्षक से अपनी 174 वीं रिपोर्ट में हिंदू कानून के अंतर्गत प्रस्तावित सुधार "(5 मई 2000)। भारत के विधि आयोग ने कहा कि "केवल अपने लिंग के कारण सह-आंशिक संपत्ति के स्वामित्व में भाग लेने से बेटियों का बहिष्कार अन्यायपूर्ण है।" जब तक विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तब तक उसने नोट किया कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने ऐसे संशोधनों को शामिल किया था जो यह सुनिश्चित करेंगे कि मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में, एक सह-भागीदार की बेटी जन्म से एक बेटे की तरह अपने अधिकार में सह-भागीदार बनेगी (पैरा 3.1 और 3.2.1 देखें)। विधि आयोग ने कहा कि केरल ने एक कदम और आगे बढ़कर किसी पूर्वज की किसी भी संपत्ति में उसके जीवनकाल के दौरान किसी भी हित का दावा करने के अधिकार को केवल इस तथ्य के आधार पर समाप्त कर दिया कि वह परिवार में पैदा हुआ था। "विधि आयोग की रिपोर्ट से एच. एस. ए. 1956 में 2005 का संशोधन हुआ।

30. एच. एस. ए. 1956 की धारा 6 को 2005 के अधिनियम 39 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। एचएसए 2005 की शुरुआत 9 सितंबर 2005 को हुई थी। धारा 6 (1) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

"6. सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण।—(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर और उसके बाद से, मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में, एक सह-भागीदार की बेटी, (ए) जन्म से बेटे के समान अपने अधिकार में सह-भागीदार बनेगी; (बी) सह-भागीदार संपत्ति में उतने ही अधिकार होंगे जितने उसे होते

अगर वह एक बेटा होता; (सी) उक्त सह-भागीदार संपत्ति के संबंध में उतने ही दायित्वों के अधीन होगा जितने एक बेटे के संबंध में, और एक हिंदू सह-भागीदार के किसी भी संदर्भ में एक सह-भागीदार की बेटा का संदर्भ शामिल माना जाएगा: बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी संपत्ति के किसी भी विभाजन या वसीयती निपटान सहित किसी भी स्वभाव या अलगाव को बाधित या अमान्य नहीं करेगा जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुआ था। "

351

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 352

विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया है कि:

“उद्देश्यों और कारणों का विवरण।

अधिनियम की धारा 6 सह-पक्षीय संपत्ति में एक पुरुष हिंदू के हित के हस्तांतरण से संबंधित है और सह-पक्षीय सदस्यों के बीच उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण के नियम को मान्यता देती है। महिलाओं को शामिल किए बिना मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति के प्रतिधारण का मतलब है कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तरह पैतृक संपत्ति में विरासत में नहीं मिल सकती हैं। बेटा को सह-स्वामित्व में भाग लेने से अलग करके विधि न केवल लिंग के आधार पर उसके भेदभाव में योगदान देता है, बल्कि संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के उसके मौलिक अधिकार का उत्पीड़न और निषेध भी करता है। "

31. संसदीय संशोधन, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है, "धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर करने का प्रस्ताव है। हिंदू मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार देकर"। संशोधन ने धारा 23 को भी हटा दिया, जिसमें एक महिला उत्तराधिकारी को संयुक्त परिवार द्वारा पूरी तरह से कब्जा किए गए आवास के संबंध में विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं दिया गया था, जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने-अपने शेयरों को विभाजित करने का विकल्प नहीं चुनते।

2005 के अधिनियम 39 की धारा 6 के प्रतिस्थापन का प्रभाव यह है कि सह-भागीदार की बेटा

((i) पुत्र के समान जन्म से अपने अधिकार में सह-भागीदार बनें।

((ख) सह-पक्षीय संपत्ति में उन्हें उतने ही अधिकार हैं जितने उन्हें पुत्र होने पर होते; और

((iii) पुत्र के रूप में सह-आंशिक संपत्ति के संबंध में समान देनदारियों के अधीन होना।

32. संशोधित धारा 6 (3) निम्नलिखित प्रावधान करती है:

“(3) जहां हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के बाद किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षर विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, इस अधिनियम के अंतर्गत, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।

/

[2023] 14 एस सी आर।

(क) बेटी को वही हिस्सा आवंटित किया जाता है जो एक बेटे को आवंटित किया जाता है;
(ख) पूर्व-मृत बेटे या पूर्व-मृत बेटी का हिस्सा, जो उन्हें विभाजन के समय जीवित होता तो मिलता, ऐसे पूर्व-मृत बेटे या ऐसी पूर्व-मृत बेटी के जीवित बच्चे को आवंटित किया जाएगा;
और (ग) पूर्व-मृत बेटे या पूर्व-मृत बेटी के पूर्व-मृत बच्चे का हिस्सा, जैसा कि ऐसा बच्चा मिलता अगर वह विभाजन के समय जीवित होता।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया जाता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से तुरंत पहले हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। ”

33. संशोधन से पहले, धारा 6 में प्रावधान किया गया था कि "एक पुरुष हिंदू" की मृत्यु पर, मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में उसका हित सह-पक्षीय के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि अधिनियम में प्रदान किए गए उत्तराधिकार के तरीके के अनुसार। संशोधित प्रावधान की धारा 6 (3) अब यह निर्धारित करती है कि संशोधन अधिनियम के शुरू होने के बाद "एक हिंदू" की मृत्यु होने पर, मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, अधिनियम के अंतर्गत वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होता है, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

34. विनीता शर्मा के मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

“60...अधिकार का प्रदान जन्म से होता है, और अधिकार उसी तरह से दिए जाते हैं जैसे एक बेटे की सह-भागीदारी की घटनाओं के साथ और उसे उसी तरह से एक सह-भागीदार के रूप में माना जाता है जैसे कि वह जन्म के समय एक बेटा था। यद्यपि अधिकारों का दावा किया जा सकता है, डब्ल्यू. ई. एफ. 9-9-2005, प्रावधान पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के हैं; वे पूर्ववर्ती घटना के आधार पर लाभ प्रदान करते हैं, और मिताक्षर सह-पक्षीय विधि में एक बेटी को सह-भागीदार के रूप में संदर्भित करना शामिल माना जाएगा। ”

35. 2005 के संशोधन अधिनियम ने एच. एस. ए. 1956 की धारा 6 को पूर्ववर्ती प्रावधान के स्थान पर रखा। उप-धारा (1) और (2) को शामिल करने से मिताक्षर विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवारों में बेटियों को सह-आंशिक अधिकार प्रदान किए गए। वह संपत्ति जिसके लिए एक महिला हिंदू उप-धारा (1) के अंतर्गत हकदार हो जाती है, उप-धारा (2) के संदर्भ में, उसके पास सह-स्वामित्व की घटनाओं के साथ रखी जाएगी और वह वसीयती स्वभाव से निपटाने में सक्षम है। धारा 6 की उप-धारा (3) ने मिताक्षर विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में ब्याज के हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत की है। जहां 9 सितंबर 2005 (संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख) के बाद किसी हिंदू की मृत्यु हो गई है, वहां उप-धारा (3) के संदर्भ में उसका हित अधिनियम के अंतर्गत वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा निहित होता है, न कि उत्तरजीविता द्वारा। संशोधन से पहले, धारा 6 के मूल भाग में यह निर्धारित किया गया था कि मृत्यु के समय मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में एक पुरुष हिंदू का हित -

(i) सहसदस्यता के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित करना; और

((ii) अधिनियम के अनुसार हस्तांतरित नहीं होता है।

हालांकि, परंतुक में एक अपवाद का उल्लेख किया गया है जहां मृतक अपने पीछे अनुसूची की प्रथम श्रेणी में निर्दिष्ट एक जीवित महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में एक पुरुष रिश्तेदार को छोड़ गया था जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता था। जहां परंतुक लागू होता है, वहां यह निर्धारित किया जाता है कि मृत पुरुष हिंदू का हित -

(i) अधिनियम के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित; और

((ii) उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

36. अधिनियम के अंतर्गत वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण का सिद्धांत जो संशोधन अधिनियम से पहले एक अपवाद था जैसा कि परंतुक में निर्धारित किया गया था, अब धारा 6 की उप-धारा (3) में मानक बन गया है। उप-धारा (3) के अनुसार बेटी उसी हिस्से की हकदार है जो एक बेटे को आवंटित किया जाता है। 2005 के संशोधन से पहले, स्पष्टीकरण I ने हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को मान कर अवहेलना की थी। स्पष्टीकरण I के अनुसार, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को संपत्ति में वह हिस्सा माना जाता था जो उसे विभाजन होने पर आवंटित किया जाता।

/

[2023] 14 एस सी आर।

संपत्ति की राशि उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुई थी, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। स्पष्टीकरण I, जैसा कि 2005 के संशोधन अधिनियम से पहले था,

विधानमंडल द्वारा संशोधन के बाद उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित का निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति का विभाजन हुआ है। उसके हित को संपत्ति में वह हिस्सा माना जाता है जो उसकी मृत्यु से ठीक पहले एक समय पर विभाजन में आवंटित किया गया होता, भले ही वह विभाजन की मांग करने का हकदार था या नहीं।

37. वर्तमान प्रयोजनों के लिए धारा 6 की उप-धारा (3) के महत्वपूर्ण शब्द हैं, "इस अधिनियम के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।" धारा 8 निर्वसीयत मरते हुए हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का प्रावधान करती है।⁴⁴ संपत्ति पहली बार अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाती है; यदि प्रथम वर्ग का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो द्वितीय वर्ग में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों पर; यदि दोनों वर्गों में से किसी में भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो राजपत्रों पर और यदि कोई राजपत्र नहीं है, तो मृतक के कुलपतियों पर। धारा 9 अनुसूची में उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार के क्रम का प्रावधान करती है। धारा 10 अनुसूची के प्रथम वर्ग में उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के वितरण के लिए निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान करती है:

"10. प्रथम श्रेणी में उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का वितरण

अनुसूची.— निर्वसीयत की संपत्ति को निम्नलिखित नियमों के अनुसार अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित किया जाएगा:—

नियम 1.— निर्वसीयत की विधवा, या यदि एक से अधिक विधवाएँ हैं, तो सभी विधवाएँ एक साथ एक हिस्सा लेंगी।

44 8. पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम।— निर्वसीयत मरते हुए हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगी -

(क) प्रथमतः, अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट रिश्तेदार होने पर; (ख) द्वितीयतः, यदि प्रथम वर्ग का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अनुसूची के द्वितीय वर्ग में निर्दिष्ट रिश्तेदार होने पर;

((ग) तीसरा, यदि दोनों में से किसी भी वर्ग का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मृतक के उत्तराधिकारियों पर; और

(घ) अंत में, यदि कोई अगनेट नहीं है, तो मृतक के संज्ञापत्र पर।

355

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 356

नियम 2.— जीवित बेटे और बेटियाँ और निर्वसीयत की माँ प्रत्येक एक हिस्सा लेंगे।

नियम 3.— प्रत्येक पूर्व-मृत पुत्र या निर्वसीयत की प्रत्येक पूर्व-मृत बेटी की शाखा में उत्तराधिकारी अपने बीच एक हिस्सा लेंगे। नियम 4.— नियम 3 में निर्दिष्ट हिस्से का वितरण-

(i) पूर्व-मृत पुत्र की शाखा में उत्तराधिकारियों के बीच इस तरह किया जाएगा कि उसकी विधवा (या विधवाओं को एक साथ) और जीवित बेटों और बेटियों को समान हिस्सा मिले और उसके पूर्व-मृत बेटों की शाखा को समान हिस्सा मिले।

((ii) पूर्व-मृत बेटी की शाखा में उत्तराधिकारियों के बीच इस तरह से बनाया जाएगा कि जीवित बेटे और बेटियों को समान भाग मिले। "

38. धारा 10 के संदर्भ में, वर्ग-I में उत्तराधिकारियों के बीच एक निर्वसीयत की संपत्ति का विभाजन ऊपर निकाले गए चार नियमों द्वारा शासित होता है। वे कहते हैं कि

((i) विधवा या यदि एक से अधिक हैं तो वे सभी मिलकर एक हिस्सा लेंगे।

((ख) जीवित पुत्र-पुत्री और माता प्रत्येक एक-एक हिस्सा लेंगे; और

((iii) प्रत्येक पूर्व-मृत पुत्र या प्रत्येक पूर्व-मृत बेटी की शाखा में उत्तराधिकारी अपने बीच एक हिस्सा लेते हैं।

39. धारा 10 के नियम 2 में कहा गया है कि "जीवित बेटे और बेटियाँ और निर्वसीयत की माँ प्रत्येक एक हिस्सा लेंगे"। "जीवित बेटे और बेटियाँ" अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए एच. एस. ए. 1956 ने बच्चे की वैधता के आधार पर कोई भेद नहीं किया है। व्याख्या के सुव्यवस्थित सिद्धांतों का पालन करते हुए संसद, एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 के प्रावधानों द्वारा दी गई वैधता और 1976 में प्रावधान के प्रतिस्थापन द्वारा संरक्षण के विस्तार से अवगत होगी। बच्चे की वैधता के संदर्भ में धारा 10 के नियम 2 के प्रावधानों को अर्हता प्राप्त करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। इसलिए एच. एस. ए. 1956 की धारा 10 के संदर्भ में एक निर्वसीयत की संपत्ति को विभाजित करने में, इस तरह के वर्गीकरण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता है, एक बार जब ऐसा बच्चा माना जाता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 के अंतर्गत वैध। ऐसा निर्माण एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 की उप-धारा 3 के प्रावधानों के अनुरूप भी होगा, जिसमें कहा गया है कि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) द्वारा वैधता प्रदान करने से ऐसे बच्चे को माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उस पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। "

40. एच. एस. ए. 1956 की धारा 10 अनुसूची के वर्ग-1 में उत्तराधिकारियों के बीच "एक निर्वसीयत की संपत्ति" के विभाजन का प्रावधान करती है। "निर्वसीयत की संपत्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ है वह संपत्ति जो निर्वसीयत से संबंधित है। धारा 6 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित का पता लगाने का प्रावधान है, जिसे संपत्ति में वह हिस्सा माना जाता है जो उसे आवंटित किया जाता यदि उसकी मृत्यु से ठीक

पहले कोई विभाजन हुआ होता। धारा 6 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में निर्धारित वह हिस्सा धारा 8 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा और धारा 10 के संदर्भ में वर्ग-1 के उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाना है। अनुसूची की श्रेणी-I निम्नलिखित शर्तों में है:

“बेटा; बेटी; विधवा; माँ; पूर्व-मृत बेटे का बेटा; पूर्व-मृत बेटी की बेटी; पूर्व-मृत बेटी की बेटी; पूर्व-मृत बेटे की विधवा; पूर्व-मृत बेटे के पूर्व-मृत बेटे का बेटा; पूर्व-मृत बेटे के पूर्व-मृत बेटे की बेटी; पूर्व-मृत बेटे के पूर्व-मृत बेटे की विधवा; पूर्व-मृत बेटी की पूर्व-मृत बेटी की बेटी; पूर्व-मृत बेटी की पूर्व-मृत बेटी की बेटी; पूर्व-मृत बेटे के पूर्व-मृत बेटे की बेटी।”

41. मृतक की संपत्ति के वितरण के उद्देश्य से, वर्ग-I 'बेटा' और 'बेटी' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। जो संपत्ति वितरण के लिए आती है, वह मृत्यु से ठीक पहले हुए एक काल्पनिक विभाजन के आधार पर सह-आंशिक संपत्ति में मृतक का हिस्सा है। वितरित की जाने वाली संपत्ति मृतक की है। धारा 6 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सह-भागीदार की मृत्यु से ठीक पहले एक काल्पनिक विभाजन हुआ है और उसके हित को वह हिस्सा माना जाता है जो ऐसे विभाजन में उसे आवंटित किया गया होता। दूसरे शब्दों में, विधायिका ने एक काल्पनिक आधार पर मृतक के हिस्से का पता लगाने का प्रावधान किया है। 357 में 'शेयर' अभिव्यक्ति

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओ. आर. एस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 358

संपत्ति जो उसे आवंटित की गई होती यदि संपत्ति का विभाजन हुआ होता 'इंगित करता है कि यह हिस्सा मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ मृतक की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है, वहाँ संपत्ति धारा 8 के अनुसार हस्तांतरित हो जाएगी और वितरण धारा 10 में निर्दिष्ट नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

एच. माता-पिता की संपत्ति

42. जब 2005 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, तो मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाना चाहिए, न कि उत्तरजीविता द्वारा, जैसा कि धारा 6 की उप-धारा (3) में निर्धारित किया गया है। उप-धारा (3) के प्रयोजन के लिए एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित का निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले एक काल्पनिक विभाजन हुआ है। संपत्ति में वह हिस्सा जो ऐसे काल्पनिक विभाजन के आधार पर निर्वसीयत को आवंटित किया गया होता, धारा 8, एच. एस. ए. 1956 में निर्दिष्ट उत्तराधिकार के सामान्य नियमों द्वारा शासित होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का वितरण धारा 10 में निर्दिष्ट नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वितरण में अन्य बातों के साथ-साथ निर्वसीयत के जीवित बेटे, बेटियाँ और माँ एक-

एक हिस्सा लेते हैं और इसी तरह विधवा (और सभी विधवाएँ एक से अधिक होने पर एक साथ) एक हिस्सा लेती हैं। निर्वसीयत मृत्यु प्राप्त मृतक की संपत्ति के वितरण में, एक बच्चा जिसे एच. एम. ए. 1955 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत या धारा 16 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वैध माना जाता है, वह हिस्से का हकदार होगा। चूँकि यह वह संपत्ति है जो काल्पनिक विभाजन के बाद निर्वसीयत के हिस्से में आएगी, यह निर्वसीयत के अंतर्गत आती है। धारा 16 (3) अंतर्गत वैधता से सम्मानित बच्चा केवल अपने माता-पिता की संपत्ति का हकदार है, और उसे माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर या उसमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, जहाँ मृतक की निर्वसीयत मृत्यु हो गई है, इस संपत्ति का हस्तांतरण बच्चों के बीच होना चाहिए-वैध के साथ-साथ एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (1) और 16 (2) के अंतर्गत विधायिका द्वारा वैधता प्रदान की गई। ऐसा करने से उस प्रतिबंध का अंत या उल्लंघन नहीं होगा जो धारा 16 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट है।

43. धारा 6 की उप-धारा (3) एक डीमिंग प्रावधान द्वारा इंगित करती है कि हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार का हित क्या होगा। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, माना जा रहा है कि एक धारणा की आवश्यकता है

/

[2023] 14 एस सी आर।

सम्बन्ध की काल्पनिक स्थिति के संदर्भ में माना जाता है कि हिंदू मिताक्षर सह-संस्थापक की मृत्यु से तुरंत पहले एक काल्पनिक विभाजन हुआ था। अब, उदाहरण के लिए मान लें कि चार सह-विभाजक हैं-C1, C2, C3 और C4। सी2 मर चुका है। सी2 के परिवार में एक विधवा, एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन यह इतना स्पष्ट है कि बच्चों में से एक का जन्म एक शादी से हुआ है जो एच. एम. ए. 1955 की धारा 11 के अंतर्गत अमान्य है। सी2 का सह-वार्षिक में 1/4 वां हिस्सा होगा जिसमें वह और उनके तीन भाई सी1, सी3 और सी4 शामिल थे। अब, संपत्ति में सी2 के हिस्से और सी2 के उत्तराधिकारियों के बीच इन शेयरों के हस्तांतरण का पता लगाने के लिए, स्पष्टीकरण एक धारणा को अनिवार्य करता है कि सी2 की मृत्यु से तुरंत पहले एक विभाजन हुआ था। इस तरह के विभाजन में, उसके और उसके भाइयों के बीच, सी 2 को अपने और अपने 3 भाइयों के बड़े सह-दल में एक चौथाई हिस्सा मिलता है। अब, उनकी अपनी शाखा, सी2 के भीतर, उनकी विधवा और वैध विवाह से पैदा हुए उनके बच्चे में से प्रत्येक का एक तिहाई हिस्सा होगा। दूसरे शब्दों में, जिस काल्पनिक विभाजन को स्पष्टीकरण के संदर्भ में किया गया माना जाता है, उसमें C2 का हिस्सा 1/3 पर निर्धारित किया जाता है। सी2 की मृत्यु के बाद ब्याज के हस्तांतरण और संपत्ति के वितरण पर काम करने में, सी2 का 1/3 हिस्सा उसकी विधवा, विवाह से पैदा हुआ बच्चा जो वैध था और विवाह से पैदा हुआ बच्चा जिसकी वैधता एचएमए 1955 की धारा 16 (1) द्वारा संरक्षित है, के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा, हालांकि विवाह अमान्य था। दूसरे शब्दों में, ऐसे बच्चे का संपत्ति में एक हिस्सा होगा जो उसके माता-पिता (सी2) को आवंटित किया जाएगा

यदि सी² की मृत्यु से ठीक पहले कोई विभाजन हुआ था।विधवा एक तिहाई हिस्सा (काल्पनिक विभाजन में उसका हिस्सा) और सी² के एक तिहाई हिस्से में एक तिहाई हिस्सा (सी² के उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकार में उसका हिस्सा) लेगी।वैध विवाह से पैदा हुआ बच्चा सी² के 1/3 वें हिस्से में 1/3 वें हिस्से के साथ 1/3 वें हिस्से का अधिग्रहण करेगा। जिस बच्चे को एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (1) का लाभ प्राप्त है, वह सी. 2 को आवंटित एक तिहाई हिस्से में एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करता है, यह मानते हुए कि विभाजन सी. 2 की मृत्यु से ठीक पहले हुआ था।यह बच्चा, एक वैध विवाह से पैदा हुए बच्चे के विपरीत, काल्पनिक विभाजन में ही हिस्से का हकदार नहीं है।इस तरह के काल्पनिक विभाजन में पिता के हिस्से का निर्धारण होने के बाद, जिस बच्चे की वैधता धारा 16 (1) और 16 (2) के अंतर्गत संरक्षित है, उसे जीवित विधवा और अन्य बच्चों के साथ पिता के हिस्से में हिस्सा मिलेगा।यह, हमारे विचार में, धारा 6 के स्पष्टीकरण की सही और उचित व्याख्या होगी।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 360

एक काल्पनिक स्थिति की धारणा को अनिवार्य करता है, अर्थात् हिंदू पुरुष सह-भागीदार की मृत्यु से ठीक पहले एक विभाजन।

44. हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस बच्चे को धारा 16 (1) और धारा 16 (2) के अंतर्गत वैधता प्रदान की गई है, उसका 'बड़े सह-वार्षिक' के विभाजन में हिस्सा नहीं होगा, लेकिन सह-वार्षिक में उसका हिस्सा होगा जिसमें बच्चे के पिता और पिता के वैध बच्चे शामिल होंगे।यह आग्रह किया गया है कि बाद वाला सह-सहभागी, यह बच्चा एक वैध विवाह से पैदा हुए पिता के अन्य बच्चों के बराबर होगा, और सह-सहभागी संपत्ति के उद्देश्य के लिए व्यवहार की ऐसी समानता विधि 45 का उद्देश्य है।

हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह सच है कि हिंदू विधि परिवार की एक शाखा को एक अधीनस्थ निगमित इकाई के रूप में मान्यता देता है, जिसमें ऐसी कई शाखाएं शामिल हैं। हालाँकि, ऐसी शाखाएँ भी कुछ सीमाओं के अधीन पारिवारिक संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान कर सकती हैं।ऐसी शाखा द्वारा धारित संपत्ति की प्रकृति, जब तक कि शाखा के सदस्यों के बीच विभाजित नहीं हो जाती है, शाखा के सभी सह-भागीदारों की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति नहीं रह जाती है।अब, चूंकि धारा 16 के अंतर्गत वैधता से सम्मानित बच्चा सह-भागीदार नहीं है, इसलिए शाखा में वैध विवाह से पैदा हुए पिता और उनके बच्चे शामिल हैं।इस प्रकार, संपत्ति, जो एक बार बड़ी सह-संपत्ति से विभाजित हो जाती है, और पिता के हाथों में, अपनी शाखा के लिए, पिता की अलग संपत्ति नहीं है, जब तक कि विभाजन शाखा के भीतर नहीं होता है।यह अभी भी सह-आंशिक संपत्ति बनी हुई है जिसमें उसके वैध विवाह के बच्चों का संयुक्त स्वामित्व है।इस प्रकार, धारा 16 (3) में प्रतिबंध को देखते हुए, इस संपत्ति में-जो पिता की अनन्य संपत्ति नहीं है-धारा 16 (1) और 16 (2) के अंतर्गत आने वाला बच्चा हकदार नहीं है।/

45 अपीलार्थी की ओर से लिखित सारांश रेवनसिदप्पा और अन्न बनाममल्लिकार्जुन और अन्य किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पृष्ठ 4 द्वारा।

46 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) 9 एस. सी. सी. 1,39 (पैरा 36)-"भगवान दयाल में

बनाम रेवती देवी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सह-प्रतिनिधि विधि का एक प्राणी है और परिवार की शाखा एक अधीनस्थ निगमित निकाय है और इस प्रस्ताव पर इस प्रकार चर्चा की गई: "47. सहसदस्यता हिंदू विधि की एक रचना है और इसे पुनर्मिलन के मामले को छोड़कर पक्षों की सहमति से नहीं बनाया जा सकता है। यह एक निगमित निकाय या एक पारिवारिक इकाई है। विधि परिवार की एक शाखा को एक अधीनस्थ निगमित निकाय के रूप में भी मान्यता देता है। उक्त परिवार इकाई, चाहे वह बड़ी हो या अधीनस्थ, विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन पारिवारिक संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान कर सकती है। आम तौर पर प्रबंधक,

/

[2023] 14 एस सी आर।

45. उपरोक्त कानूनी स्थिति धारा 6, एच. एस. ए. और धारा 16, एच. एम. ए. के संयुक्त पठन द्वारा भी समर्थित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां एच. एम. ए. की धारा 16 (1) और धारा 16 (2) बच्चों को अमान्य या अमान्य विवाहों से वैधता प्रदान करती है, वहीं उप-धारा (3) ने उस संपत्ति के अधिकार की सीमा को सीमित कर दिया है जो उस व्यक्ति को प्राप्त होगी जिसे उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत वैधानिक रूप से वैधता प्रदान की गई है। ऐसे व्यक्ति को माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उस पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, ऐसे व्यक्ति के हिस्से को निर्धारित करने में जो धारा 16 की दो उप-धाराओं द्वारा वैधता के वैधानिक प्रदान के लाभ का हकदार है, यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में माता-पिता की संपत्ति क्या है जो एच. एस. ए. 1956 की धारा 6 (3) के अंतर्गत निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण के लिए आती है। जहां माता-पिता हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार हैं, स्पष्टीकरण में कहा गया है कि संपत्ति में उनके हिस्से का निर्धारण उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुए एक काल्पनिक विभाजन के आधार पर किया जाना चाहिए। हिंदू पुरुष सह-भागीदार का हिस्सा जो उनकी मृत्यु से ठीक पहले एक काल्पनिक विभाजन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, एच. एस. ए. 1956 की धारा 10 के संदर्भ में उनके उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाएगा। वह व्यक्ति जिसे एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (1) या धारा 16 (2) द्वारा वैधता प्रदान की गई है, वह संपत्ति में उस हिस्से का हकदार होगा जो माता-पिता की मृत्यु से तुरंत पहले एक काल्पनिक विभाजन मानते हुए उनके माता-पिता को आवंटित किया गया होगा। ऐसा निर्माण धारा 6 (3) के अनुसार होगा और इसे एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (3) के प्रावधानों के साथ सुसंगत बनाएगा।

46. हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि एच. एम. ए. 1955 18 मई 1955 से प्रभावी अधिनियम के साथ लागू हुआ। धारा 16, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित की गई थी, अमान्य या अमान्य विवाहों से पैदा हुए बच्चों की वैधता प्रदान करने से संबंधित है, जैसा भी मामला हो। पूर्ववर्ती प्रावधान में एक परंतुक था जो इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे के संपत्ति में अधिकार की सीमा को सीमित करता था। एच. एस. ए. 1956 17 जून 1956 को

प्रभावी हुआ। धारा 6, जो मूल रूप से थी, को 2005 के अधिनियम 39 द्वारा प्रभावी अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

या परिवार के सदस्यों की सहमति से, व्यक्त या निहित, कोई अन्य सदस्य या सदस्य परिवार के लिए या उसकी ओर से, उक्त विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन, व्यवसाय कर सकता है या संपत्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यवसाय या संपत्ति परिवार का व्यवसाय या संपत्ति होगी।

361

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 362 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

9 सितंबर 2005 से। जबकि धारा 4 अधिनियम को अधिस्थापक प्रभाव देती है, उप-धारा (1) का खंड (बी) इंगित करता है कि यह हिंदुओं पर लागू होने वाले अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू किसी अन्य विधि के संबंध में है, जहां तक कि यह एच. एस. ए. 1956 के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है। एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (3) और एच. एस. ए. 1956 की धारा 6 (3) के बीच कोई विसंगति नहीं है और दोनों को ऊपर बताए गए तरीके से सुसंगत बनाया जाना चाहिए। जब धारा 6 को एच. एस. ए., 1956 के पाठ में शामिल किया गया था, जैसा कि इसे मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, तो संसद एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 के पहले से मौजूद प्रावधानों से अवगत थी। जब 2005 के अधिनियम 39 द्वारा धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया था, तो संसद को 1976 के अधिनियम 68 द्वारा एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 के प्रतिस्थापन के बारे में पता था, जो 27 मई 1976 से प्रभावी था।

47. इस स्तर पर, एच. एस. ए. 1956 की धारा 3 (जे) के प्रावधानों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा जो निम्नलिखित शब्दों में 'संबंधित' अभिव्यक्ति की अवहेलना करते हैं:

“(जे) "संबंधित" का अर्थ वैध संबंध से संबंधित है:

बशर्ते कि अवैध बच्चों को उनकी माँ और एक दूसरे से संबंधित माना जाएगा, और उनके वैध वंशजों को उनसे और एक दूसरे से संबंधित माना जाएगा; और संबंध व्यक्त करने वाले या किसी रिश्तेदार को दर्शाने वाले किसी भी शब्द का अर्थ तदनुसार किया जाएगा।

48. धारा 3 (जे) के परंतुक से संकेत मिलता है कि अवैध बच्चों को उनकी माँ और एक दूसरे से संबंधित माना जाएगा। यह प्रावधान उस व्यक्ति के रास्ते में नहीं आएगा जो एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (1) या (2) द्वारा एच. एस. ए. की धारा 6 (3) के निर्णय दर्भ में अपने माता-पिता की निर्णय पत्ति में हिस्सेदारी मांगने में निर्णय रक्षित है। एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को वैधता प्रदान किए जाने के बाद, धारा 3 (जे) का परंतुक जो "अवैध बच्चों" से संबंधित है, धारा 16 (1) और धारा 16 (2) के अंतर्गत आने वाले बच्चों पर लागू नहीं होता है।

49. एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (3) और एच. एस. ए. 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक स्पष्ट निर्णय में विस्तार से चर्चा की गई है।

शांताराम तुकाराम पाटिल बनाम दगुबाई तुकाराम पाटिल **47**.न्यायमूर्ति आर. ए.

डिवीजन बेंच की ओर से बोलते हुए जहांगीरदार ने कहा:“21...

हम पहले ही यह मान चुके हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त वैधता 1976 के संशोधन से पहले भी थी।केवल इसे कुछ और लोगों तक बढ़ाया गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो बाद में हिंदू विवाह अधिनियम में परिवर्तित हो गया। इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि संसद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 में निहित प्रावधानों से अवगत थी-एक पूर्व विधि -और इसके बावजूद यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत वैध बनाए गए बच्चों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वैध उत्तराधिकारियों के वर्ग से बाहर नहीं करती थी। वास्तव में यह माना जा सकता है कि यदि संसद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के "वैध बच्चों" को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से बाहर करना चाहती है, तो उसने उस प्रभावी अधिनियम के लिए अनिवार्य रूप से प्रावधान किया होगा।इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 द्वारा बनाई गई वैधता को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 (1) (जे) में अवज्ञा के एक हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यह मान लेना अनुचित होगा कि धारा 3 (1) (जे) किसी पूर्ववर्ती अधिनियम में निहित प्रावधान के प्रभाव को रद्द कर देगी, जब वह या तो व्यक्त शब्दों या आवश्यक निहितार्थ से ऐसा नहीं करती है। "

डिवीजन बेंच ने कहा कि एक अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे और जिन्हें एच. एम. ए. की धारा 16 के प्रावधानों के आधार पर वैध माना जाता है, वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 (1) (जे) की स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित अवज्ञा के बावजूद धारा 16 (3) द्वारा उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों के हकदार हैं।

डिवीजन बेंच ने कहा कि अमान्य विवाह के बच्चों को उनके माता-पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है:

“24... चूंकि कोई भी बच्चा जन्म से अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं करता है, इसलिए इन अधिकारों का प्रयोग केवल संपत्ति के उत्तराधिकार के माध्यम से किया जा सकता है।

47 1987 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 9:1987 माह एलजे179 363

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 364

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची के अनुसार और वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधानों के अनुसार सफल होने के हकदार हैं।

I. वैधता और सहयोगात्मकता

50. प्रथम सिद्धांत के रूप में, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अंतर्गत शून्य या, जैसा भी मामला हो, विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करते हुए, संसद ने संपत्ति में अधिकारों की प्रकृति को सीमित कर दिया जो ऐसा बच्चा मांग सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है

इसो वास्तव में हिंदू मिताक्षर संयुक्त परिवार में एक सह-भागीदार बन गया।

इस तरह के एच. यू. एफ. को नियंत्रित करने वाला मूल सिद्धांत यह है कि एक सह-भागीदार दूसरों के साथ एक समान संपत्ति रखता है। एक ऐसे व्यक्ति का जन्म जो सह-भागीदार है, सह-सहभागी संपत्ति में ब्याज के अधिग्रहण की ओर ले जाता है। शेष जन्म के साथ बढ़ने और सह-भागीदार की मृत्यु के साथ कम होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। धारा 6 (3) के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, मृत्यु पर मिताक्षर विधि द्वारा शासित एच. यू. एफ. की संपत्ति में एक हिंदू पुरुष सह-भागीदार के हिस्से का हस्तांतरण उत्तरजीविता द्वारा नहीं बल्कि अधिनियम के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा होता है। इसलिए धारा 6 (3) में इसके प्रतिस्थापन के बाद अधिनियम के अंतर्गत वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण का प्रावधान है न कि उत्तरजीविता द्वारा। हालांकि, धारा 6 मिताक्षर हिंदू संयुक्त परिवारों के अस्तित्व को मान्यता देना जारी रखती है। 51. एच. एम. ए. 1955 के अधिनियमन से पहले, हिंदू विधि एक पूर्व विवाह के अस्तित्व के दौरान एक पुरुष हिंदू की दूसरी शादी को अमान्य नहीं बनाता था। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य 48 में अपने निर्णय में कानून के अधिनियमन से पहले की स्थिति को मान्यता दी। न्यायालय ने कहा कि "हिंदू विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अधिनियमन तक विवाहों पर लागू होता है, जिसने अपनी पिछली पत्नी के जीवनकाल के दौरान एक पुरुष हिंदू की दूसरी शादी को अमान्य बना दिया था।" कानून के अधिनियमन पर, धारा 5, एक वैध विवाह की शर्तों को निर्धारित करते हुए यह प्रावधान करने के लिए आई कि किसी भी दो हिंदुओं के बीच विवाह किया जा सकता है यदि धारा में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, उनमें से एक यह है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी नहीं है।

48 (1965) 2 एससीआर 837

/

[2023] 14 एस सी आर।

धारा 17 में कहा गया है कि अधिनियम के प्रारंभ के बाद दो हिंदुओं के बीच किया गया कोई भी विवाह अमान्य है, यदि इस तरह के विवाह की तारीख पर किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित है। नतीजतन, द्विविवाह से संबंधित दंड संहिता की धारा 494 और 495 के प्रावधान लागू होने हैं। एच. एम. ए. 1955 के अधिनियमन पर, धारा 16 जैसे सुरक्षात्मक प्रावधान के अभाव में, हिंदुओं को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत विधि को उस हद तक पूर्व विवाह के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी करने पर वैधानिक निषेध द्वारा ओवरराइड किया जाएगा। धारा 4 ने विधान के प्रावधानों पर प्रबल बल और प्रभाव प्रदान किया। द्विविवाह पर वैधानिक निषेध और विधि की नजर में इस तरह के विवाह की वैधता के परिणामस्वरूप, एक अमान्य विवाह में माता-पिता से पैदा हुआ बच्चा पारंपरिक हिंदू विधि के अंतर्गत प्राप्त वैधता से वंचित था। इस परिणाम को ध्यान में रखते हुए, धारा 16 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसका दायरा बढ़ाया गया था। वैधता प्रदान करते समय, संसद फिर भी वैधता प्रदान करने के परिणाम से अवगत थी। यदि वैधता प्रदान नहीं की जाती है, तो यह एक ओर, अमान्य या अमान्य विवाहों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को प्रभावित करेगा: हालाँकि माता-पिता के रिश्ते को विधि द्वारा मंजूरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की शादी से पैदा हुए बच्चे को "अवैध" के रूप में कलंकित किया गया होगा। संसद ने धारा 16 को लागू करके इस तरह के परिणाम को रोकने के लिए कदम उठाया। साथ ही, संसद इस तथ्य से अवगत थी कि एक अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को 'अवैधता' के परिणाम से बचाने और ऐसे बच्चे को वैधता प्रदान करने से माता-पिता और माता-पिता के अलावा अन्य व्यक्तियों की संपत्ति के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। धारा 16 (3) विधायिका द्वारा एक संतुलनकारी अधिनियम का प्रतिनिधित्व करती है जब यह निर्धारित करता है कि एक बच्चा जो धारा 16 की उप-धारा (1) या (2) के संदर्भ में वैध है, उसे केवल माता-पिता की संपत्ति में या उस पर अधिकार होगा न कि किसी अन्य व्यक्ति की। अतः वैधता का दर्जा प्रदान करने से माता-पिता की संपत्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। एच. एम. ए. 1955 में इन प्रावधानों को लागू करते समय, संसद मिताक्षर विधि, सह-पक्षीय और सह-पक्षीय संपत्ति द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवारों को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों और अवधारणाओं से अवगत थी। एच. एस. ए. 1956 को लागू करते समय, विधायिका का इरादा इन संस्थानों को नष्ट करने का नहीं था, जिनका एक पहचान-आधारित अर्थ था। यह सच है कि संसद ने सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज के हस्तांतरण को विनियमित किया और अन्य 365 के साथ प्रावधान किया।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओ. आर. एस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 366

हिंदू पुरुषों और महिलाओं के मामले में उत्तराधिकार के नियम, उत्तराधिकार का क्रम और संपत्ति के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। 1956 के बीच, जब एच. एस. ए. लागू किया गया था और 2005 के बीच जब धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया था, कई राज्य

संशोधनों ने यह स्वीकार करते हुए सह-भागीदारों की बेटियों को समान अधिकार प्रदान किए कि वे जन्म से अपने स्वयं के अधिकार में सह-भागीदार बनेंगी और उन्हें सह-आंशिक संपत्ति में वही अधिकार होंगे जो बेटों को दिए गए थे। संसद ने 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह स्वीकार करते हुए एकरूपता लाई कि एक सह-भागीदार की बेटी जन्म के समय एक बेटे के समान ही सह-भागीदार बनेगी और सह-भागीदार संपत्ति में उसी तरह के अधिकार होंगे जैसे कि वह एक बेटा रही हो और उसी दायित्व के अधीन हो। अगला बड़ा परिवर्तन जो 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था, वह यह था कि मिताक्षर विधि द्वारा शासित एचयूएफ में एक हिंदू के हित का हस्तांतरण वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा, जैसा कि मूल रूप से विधि के अधिनियमन के समय धारा 6 में निर्धारित किया गया था। इन वैधानिक विकासों से संकेत मिलता है कि संसद ने मिताक्षर विधि द्वारा शासित हिंदू अविभाजित परिवार की संस्था के अस्तित्व, एक सह-पक्ष, सह-पक्ष और सह-पक्षीय संपत्ति की अवधारणाओं को मान्यता दी है। संविधान के अनुच्छेद 15 के उद्देश्यों को मान्यता देते हुए एक अधिक लैंगिक-समान समाज की सुविधा के लिए एक वैधानिक उपाय के रूप में, संसद ने बेटियों को सह-भागीदारों के रूप में उनकी स्थिति को मान्यता देकर अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाया है ताकि बेटों के साथ समान आधार पर सह-संपत्ति में अधिकार प्राप्त किए जा सकें। संसद द्वारा किए गए संशोधनों ने कन्याओं को विशेष रूप से अधिकार प्रदान करके मिताक्षर विधि द्वारा शासित हिंदू अविभाजित परिवार में सह-सदस्य के दायरे को फिर से परिभाषित किया है।

धारा 6 (1) जो एक सह-भागीदार की बेटी को जन्म से अपने अधिकार से और बेटे के समान ही सह-भागीदार बनने का अधिकार प्रदान करती है और सह-भागीदार संपत्ति में समान अधिकार रखने के लिए प्रचुर वैधानिक सामग्री प्रदान करती है जो यह इंगित करती है कि विधायिका ने एचयूएफ, सह-भागीदार और सह-भागीदार संपत्ति की बुनियादी अवधारणाओं को समाप्त नहीं किया है। विधायिका ने बेटों के बराबर सह-भागीदार बनने के लिए बेटियों के अधिकारों को मान्यता देकर एक महत्वपूर्ण सुधार लाया। संशोधन से पहले, एक बेटा जन्म से सह-भागीदार बन जाता था, लेकिन संशोधन के बाद, बेटी के जन्म से सह-भागीदार बनने के अधिकार को मान्यता दी गई है। पुत्र और पुत्री दोनों के जन्म से अधिकार का अधिग्रहण जो धारा 6 की उप-धारा (1) में वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, स्पष्ट रूप से दर्शनीय है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

इस तथ्य का कि विधायिका ने सह-भागीदार की अवधारणा को स्वीकार करते हुए सुधार का एक महत्वपूर्ण उपाय नहीं किया है।

संशोधनों ने एच. यू. एफ. की संरचना पर निर्माण किया है और संस्थान के दायरे में लैंगिक समानता लाने के विधायी इरादे को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे कैलिब्रेट किया है। लेकिन विधायिका ने यह निर्धारित नहीं किया है कि एक बच्चा जिसकी वैधता एच. एम. ए.

1955 की धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) द्वारा संरक्षित है, जन्म से सह-भागीदार बन जाएगा। दूसरी ओर, एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 की उप-धारा (3) में उपयोग की गई स्पष्ट भाषा यह है कि वैधता प्रदान करने का अर्थ माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसे कोई अधिकार प्रदान करना नहीं होगा। जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, सह-भागीदार की अवधारणा ही जन्म से ब्याज के अधिग्रहण को स्वीकार करती है। यदि एक अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुआ व्यक्ति, जिसे धारा 16 की उप-धारा (1) या (2) द्वारा वैधता प्रदान की गई है, का मिताक्षर विधि द्वारा शासित हिंदू अविभाजित परिवार में जन्म से हित होना था, तो यह निश्चित रूप से बच्चे के माता-पिता के अलावा अन्य लोगों के अधिकारों को प्रभावित करेगा। यह मानना कि धारा 16 की उप-धारा (1) या (2) के अंतर्गत वैधता का परिणाम ऐसे व्यक्ति को सह-सहभागी के रूप में समान आधार पर रखना है, एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 की उप-धारा (3) के स्पष्ट इरादे के विपरीत होगा जो केवल माता-पिता की संपत्ति पर या उसमें अधिकारों को मान्यता देता है। वास्तव में, धारा 16 (3) द्वारा नकारात्मक भाषा का उपयोग स्थिति को संदेह के दायरे से परे रखता है। इसलिए हमें यह अभिनिर्धारित करना होगा कि जब कोई व्यक्ति धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के सुरक्षात्मक दायरे में आता है, तो वह माता-पिता की पूर्ण संपत्ति में या उसके अधिकार का हकदार होगा और कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

जे. संदर्भित निर्णय पर पुनर्विचार किया गया

52. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने निर्देशात्मक निर्णय में कहा है कि:

(i) जिनिया केओटिन (जिसका नीलम्मा में पालन किया गया है) और बाद में भारत मठ में निर्णय ने एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (3) का संकीर्ण दृष्टिकोण लिया है;

((ii) विधायिका ने धारा 16 (3) में "संपत्ति" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है, लेकिन इस बात पर चुप है कि क्या ऐसी संपत्ति पैतृक है या स्व-अर्जित है;

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 368

((iii) धारा 16 में एक स्पष्ट आदेश है कि ऐसे बच्चे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति के हकदार हैं, न कि किसी अन्य संबंध के।

(iv) जिन बच्चों को धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अंतर्गत वैध घोषित किया जाता है, उनके साथ "भेदभाव नहीं किया जा सकता है और वे अन्य वैध बच्चों के बराबर होंगे" और वे अपने माता-पिता, दोनों की संपत्ति में सभी अधिकारों के हकदार हैं।

(v) माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में ऐसे बच्चों पर धारा 16 (3) में निषेध लागू होगा; (vi) बदलते सामाजिक मानदंडों के साथ जो अतीत में अवैध था वह आज वैध हो सकता है और हिंदू विधि स्वयं समाज में परिवर्तन के साथ स्थिर नहीं रहा है;

(vii) एच. एम. ए. 1955 एक लाभकारी प्रतिशत कानून है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार लाना है और इसलिए धारा 16 (3) की व्याख्या पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

(viii) संशोधित धारा 16 सामान्य विधि की स्थिति को बदल देती है कि विवाह का एक बच्चा जो अमान्य या अमान्य है, अवैध है, लेकिन वह लाभ केवल तभी उपलब्ध है जब विवाह हो और विवाह एच. एम. ए. 1955 को देखते हुए अमान्य या अमान्य हो;

(ix) संयुक्त परिवार की संपत्ति के मामले में ऐसे बच्चे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्से के हकदार होंगे, लेकिन वे अपने अधिकार में इसका दावा नहीं कर सकते। पैतृक संपत्ति के विभाजन पर, ऐसे बच्चों के माता-पिता के हिस्से में आने वाली संपत्ति को उनकी स्व-अर्जित और पूर्ण संपत्ति माना जाता है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसे बच्चों का ऐसी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा क्योंकि ऐसे बच्चों को संशोधित विधि के अंतर्गत वैध विवाह के वैध वसंत के साथ माना जाता है। हालांकि, एकमात्र सीमा यह है कि अपने माता-पिता के जीवनकाल के दौरान ऐसे बच्चे विभाजन की मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे माता-पिता की मृत्यु के बाद ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

/

[2023] 14 एस सी आर।

(x) न्यायालय की व्याख्या व्यक्तिगत गरिमा के संवैधानिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। इसलिए, हालांकि, माता-पिता के बीच संबंध को विधि द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के रिश्ते में बच्चे के जन्म को स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। हालांकि, बच्चों के संपत्ति अधिकारों की कुछ सीमाएँ अभी भी मौजूद हैं क्योंकि उनका अधिकार उनके माता-पिता की संपत्ति तक सीमित है; और

(xi) धारा 16 (3), जैसा कि संशोधित किया गया है, ऐसे बच्चों के संपत्ति के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, सिवाय इसके कि इसे उनके माता-पिता की संपत्ति तक सीमित कर दिया जाए और इसलिए ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा, चाहे वह स्व-अर्जित हो या पैतृक।

53. संदर्भित निर्णय में कुछ हद तक विरोधाभास है जिसे स्पष्ट करने और इस स्तर पर शांत करने की आवश्यकता है। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने एक ओर विशेष रूप से कहा है कि "धारा 16 (3) में निहित निषेध ऐसे बच्चों पर उनके माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में लागू होगा।" 49 न्यायालय ने यह भी कहा है कि "संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के मामले में ऐसे बच्चे केवल अपने माता-पिता की 50 प्रतिशत संपत्ति में हिस्से के हकदार होंगे, लेकिन वे अपने अधिकार पर इसका दावा नहीं कर सकते।" न्यायालय ने तब यह अभिनिर्धारित किया कि तार्किक रूप से पैतृक संपत्ति के विभाजन पर, ऐसे बच्चों के माता-पिता के हिस्से में आने वाली संपत्ति को उनकी स्व-अर्जित और पूर्ण संपत्ति माना जाता है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसे बच्चों का ऐसी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा

क्योंकि उन्हें विधि के अंतर्गत वैध ऑफ-स्प्रिंग के बराबर माना जाता है। साथ ही, माता-पिता के जीवनकाल के दौरान, ऐसा बच्चा विभाजन की मांग नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यह अधिकार उनके माता-पिता की संपत्ति तक सीमित है। उपरोक्त टिप्पणियों से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय ने मान्यता दी है कि अमान्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के संदर्भ में वैधता प्रदान करते हुए, संसद ने यह देखते हुए ऐसे बच्चों की संपत्ति की पात्रता को सीमित कर दिया है कि उन प्रावधानों में निहित कुछ भी माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसे अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा। नोटिस किया है

49 रेवनसिदप्पा बनाम मलिक अर्जुन, (2011) 11 एस. सी. सी. 1 50 पैरा 38 पृष्ठ 11 369

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 370

न्यायालय ने यह भी कहा है कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के मामले में ऐसे बच्चे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्से के हकदार होंगे, लेकिन वे अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने माता-पिता के जीवनकाल के दौरान विभाजन की मांग नहीं कर सकते हैं। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा है कि एक बार ऐसे बच्चों को वैध घोषित कर दिए जाने के बाद, वे अन्य वैध बच्चों के बराबर होंगे। संदर्भित निर्णय के पैराग्राफ 29 में यह अवलोकन कि एक बच्चा जिसे धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अंतर्गत वैधता प्रदान की गई है, वह अन्य वैध बच्चों के बराबर होगा, अपने माता-पिता की संपत्ति में ऐसे बच्चे के अधिकारों को मान्यता देने के संदर्भ में है न कि किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति को। संदर्भित आदेश में तर्क को उन व्यक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है जिन्हें धारा 16 की दो उप-धाराओं में से किसी एक के संदर्भ में वैधता प्रदान की गई है, जो एक वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के बराबर संपत्ति में पूर्ण अधिकारों के हकदार हैं। धारा 16 (3) ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि ऐसे बच्चे के अधिकार जिन्हें धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) द्वारा वैधता प्रदान की गई है, माता-पिता की संपत्ति के संबंध में होंगे न कि किसी अन्य व्यक्ति के।

के. निष्कर्ष

54. अब हम निम्नलिखित शब्दों में अपने निष्कर्ष तैयार करते हैं:

(i) धारा 16 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, विवाह का एक बच्चा जो धारा 11 के अंतर्गत अमान्य है, उसे वैधानिक रूप से वैधता प्रदान की जाती है, भले ही (i) ऐसा बच्चा संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पहले या बाद में पैदा हुआ हो; (ii) अधिनियम के अंतर्गत उस विवाह के संबंध में निरर्थकता की डिक्री दी जाती है और विवाह को अधिनियम के अंतर्गत याचिका के अलावा अन्यथा शून्य माना जाता है।

((ii) धारा 16 की उप-धारा (2) के संदर्भ में जहां धारा 12 के अंतर्गत अमान्य होने की डिक्री द्वारा एक अमान्य विवाह को रद्द कर दिया गया है, डिक्री बनाए जाने से पहले 'उत्पन्न या गर्भ धारण' किए गए बच्चे को डिक्री के बावजूद उनका वैध बच्चा माना जाता है, अगर बच्चा विवाह के पक्षों के लिए वैध होता यदि रद्द होने की डिक्री के बजाय विघटन की डिक्री पारित की गई होती।

/

[2023] 14 एस सी आर।

(iii) अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को उप-धारा (1) के संदर्भ में वैधता प्रदान करते हुए और उप-धारा (2) के अंतर्गत एक अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैधता प्रदान करते हुए, जिसे रद्द कर दिया गया है, विधायिका ने धारा 16 की उप-धारा (3) में निर्धारित किया है कि ऐसे बच्चे को माता-पिता की संपत्ति पर या उसमें अधिकार होंगे, न कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में।

(iv) परंतुक सहित एच. एस. ए. 1956 की धारा 3 (1) (जे) के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, वैधता जो एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 द्वारा शून्य से पैदा हुए बच्चे को प्रदान की जाती है या, जैसा भी मामला हो, अमान्य विवाह को एच. एस. ए. 1956 के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक बच्चा जो एच. एम. ए. की धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अंतर्गत वैध है, एच. एस. ए. 1956 की धारा 3 (1) (जे) के प्रयोजनों के लिए, 'वैध संबंध से संबंधित' स्पष्टीकरण के दायरे में आता है और उसे परंतुक के उद्देश्यों के लिए 'अवैध बच्चा' नहीं माना जा सकता है।

(v) एच. एस. ए. 1956 की धारा 6 मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संस्था और एक सह-भागीदार की अवधारणाओं, जन्म से सह-भागीदार के रूप में ब्याज का अधिग्रहण और सह-आंशिक संपत्ति में अधिकारों को मान्यता देना जारी रखती है। धारा 6 के प्रतिस्थापन द्वारा, धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा इंगित किए गए तरीके से बेटों के समान अधिकार बेटियों को दिए गए हैं।

(vi) एच. एस. ए. 1956 की धारा 6 सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज के हस्तांतरण का प्रावधान करती है। 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा 9 सितंबर 2005 से धारा 6 को प्रभावी अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित करने से पहले, धारा 6 ने सह-सदस्य के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा एक पुरुष हिंदू की मिताक्षर सह-सदस्य संपत्ति में ब्याज के हस्तांतरण को निर्धारित किया। उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण का अपवाद वह था जहां मृतक ने अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट महिला रिश्तेदार या प्रथम वर्ग में एक पुरुष रिश्तेदार को एक महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करते हुए जीवित छोड़ दिया था, जिस स्थिति में मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में मृतक का हित वसीयती या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा विभाजित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाममल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 372

धारा 6 की उप-धारा (3) की शर्तें, जैसा कि संशोधित किया गया है, 2005 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद मरने वाले हिंदू पर मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, अधिनियम के अंतर्गत वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा। धारा 6 के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में एक मृत हिंदू के हित के वसीयती या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण के नियम को मानक बना दिया गया है;

(vii) एच. एस. ए. 1956 की धारा 8 निर्वसीयत मरते हुए हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकार के सामान्य नियम प्रदान करती है। धारा 10 अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के वितरण का प्रावधान करती है। धारा 15 महिला हिंदुओं की निर्वसीयत मृत्यु के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों को निर्धारित करती है। धारा 16 उत्तराधिकार के आदेश और एक महिला हिंदू के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का प्रावधान करती है; (viii) मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में एक हिंदू के हित के हस्तांतरण का प्रावधान करते हुए, 2005 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा मृत्यु हो जाती है, धारा 6 (3) एक विधि की निर्णय देती है जिसका अर्थ है कि 'सह-आंशिक संपत्ति को विभाजित किया गया माना जाएगा जैसे कि विभाजन हुआ था'। स्पष्टीकरण के अनुसार, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को संपत्ति में वह हिस्सा माना जाता है जो उसे आवंटित किया जाता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति का विभाजन हुआ हो, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार हो या नहीं।

(ix) एक मृत हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित का पता लगाने के उद्देश्य से, विधि सह-भागीदार की मृत्यु से तुरंत पहले संबंध की स्थिति की धारणा को अनिवार्य करता है, अर्थात् मृतक और सह-सदस्य के अन्य सदस्यों के बीच सह-पक्षीय संपत्ति का विभाजन। एक बार संपत्ति में मृतक का हिस्सा जिसे आवंटित किया गया होगा

/

[2023] 14 एस सी आर।

यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले कोई विभाजन हुआ था, तो उसके उत्तराधिकारी, जिनके बच्चे एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 के अंतर्गत वैधता से सम्मानित किए गए हैं, उस संपत्ति में अपने हिस्से के हकदार होंगे जो मृतक को काल्पनिक विभाजन पर आवंटित किया गया होता, यदि वह हुआ होता; और

(x) एच. एस. ए. 1956 के प्रावधानों को एच. एम. ए. 1955 की धारा 16 (3) के अधिदेश के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए जो इंगित करता है कि एक बच्चा जिसे उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत वैधता प्रदान की गई है, वह माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके अधिकारों का हकदार नहीं होगा। माता-पिता की संपत्ति, जिसमें माता-पिता का हित मिताक्षर विधि के अंतर्गत शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में था, का पता उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर व्याख्या की गई है।

55. समापन से पहले, यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि मामलों के इस समूह में तीन न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ मिताक्षर विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवारों के लिए है। इसलिए इस न्यायालय ने उस वर्ग के संयुक्त हिंदू परिवारों के संबंध में एच. एस. ए. 1956 के प्रावधानों की व्याख्या पर विचार किया है।

56. संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया जाएगा।

57. अलग-अलग मामलों में कार्यवाही अब निपटान के लिए कार्य के समनुदेशन के अनुसार दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष तुरंत सूचीबद्ध की जाएगी।

58. तीन न्यायाधीशों की पीठ को इस संदर्भ के लंबित होने के कारण प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित रहने की संभावना है। इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के पंजीयकों (न्यायिक) को तुरंत प्रसारित करें, जो प्रशासनिक पक्ष के मुख्य न्यायाधीशों से उपयुक्त निर्देश लेने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां तय किए गए मुद्दों से जुड़े सभी लंबित मामले कार्य सूची के अनुसार नियुक्त पीठों के समक्ष सुनवाई और निपटारे के लिए सूचीबद्ध हैं।

59. हम मामलों के समूह में पेश होने वाले सभी वकीलों द्वारा इस न्यायालय को दी गई सक्षम सहायता की सराहना करते हैं: सुश्री किरण 373

रेवनासिडडापा और ए. एन. आर. बनाम मल्लीकारजुन और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए. आई. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सुधांशु एस. चौधरी, डॉ. रवींद्र चिंगले, श्री निखिल मजीठिया, वकील; श्री के. राधाकृष्णन, सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विवेक चिब, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शिरीष के. देशपांडे, श्री सम्राट कृष्णराव शिंदे, श्री पी. बी. सुरेश, श्री निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, श्री मुकेश के. गिरि, श्री वी. प्रभाकर और श्री विवेक सोलंशे, वकील।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

संदर्भ ने जवाब दिया।

